वर्ष 12 • अंक 277 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

बुधवार 8 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 6

रिफाइनरों को मलेशिया से पाम तेल खरीद रोकने की ताकीद

अजय त्यागी ▶▶ पृष्ठ 3

योजनाओं के वर्गीकरण के नियम बदलेगा सेबी

डॉलर रु. 71.80 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 80.30 ▼ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40375 ▼ 303 रुपये | सेंसेक्स 40869.50 ▲ 192.80 | निफ्टी 12053.00 ▲ 59.90 | निफ्टी फ्यूचर्स 12106.70 ▲ 53.80 | ब्रेंट क्रूड 68.70 डॉलर ▼ 0.30 डॉलर

एक नज़र

एयर इंडिया विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ी

गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए अभिरुचि पत्र और शेयर खरीद समझौते के लिये तैयार प्रारूप को मंजूरी दे दी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि अभिरुचि पत्र और शेयर खरीद समझौते के इन प्रारूपों को एयर इंडिया के लिये बोली लगाने वालों के वास्ते जनवरी में जारी किया जाएगा। पृष्ठ 4

उतार-चढ़ाव के बीच बढ़त पर बंद हुआ बाजार

बंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में लगातार दो कारोबारी सत्रों में जोरदार गिरावट के बाद मंगलवार को सुधार देखा गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और आगे नहीं बढ़ने की उम्मीद से निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 553 अंक तक चढ़ गया था लेकिन कारोबार की समाप्ति पर यह 192.84 अंक चढ़कर 40,869.47 पर बंद हुआ। निफ्टी भी अपनी शुरुआती तेजी बरकरार नहीं रख पाई और महज 59.90 अंक की बढ़त के साथ 12,052.95 पर बंद हुआ। बाजार के भागीदारों ने कहा कि सोमवार को भारी बिकवाली के बाद मंगलवार को शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार में तेजी आई। कच्चे तेल के दाम भी 0.3 फीसदी घटकर 68.73 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपये में भी सुधार हुआ।

टीडीसैट के आदेश को चुनौती वाली याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के एक आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। इस आदेश में टीडीसैट ने केंद्र से रिलायंस कम्युनिकेशंस को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के पीठ ने कहा कि इस अपील में कोई योग्य आधार नहीं मिला। टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र को 774 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम शुल्क के एवज में 908 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के बाद कंपनी को करीब 104 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

निर्भया मामले के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी

वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए सनसनीखेज निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड मामले के चार दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने के आदेश की घोषणा की। मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है।

ईरान में भगदड़ से 50 से अधिक लोगों की मौत

ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की शवयात्रा के जुलूस में मंगलवार को मची भगदड़ में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 190 अन्य घायल हो गए। वहां के सरकारी टेलीविजन के अनुसार भगदड़ सुलेमानी के गृह नगर करमान में मची। सैन्य कमांडर शुक्रवार को इराक में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। पृष्ठ 12

व्यापार गोष्ठी

अर्थव्यवस्था सुधारने को कर में हों क्या बदलाव?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें gosshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या फंसे कर्ज का समाधान नहीं होने से बढ़ेगी बैंकों की मुश्किल

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या 'निर्विक' योजना से सुगम होगी निर्यात की राह?
हां **66.67%**
नहीं **33.33%**

5 फीसदी जीडीपी का अनुमान

चालू वित्त वर्ष में दशक में सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 7 जनवरी

चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर घटकर 5 फीसदी रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष यह 6.8 फीसदी थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आज आंकड़ों में यह अनुमान जताया गया है। यह 2008-09 के बाद सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सबसे कम वृद्धि दर है। तब वैश्विक आर्थिक संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। हालांकि, यह आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमानों के मुताबिक है।

लेकिन 2019-20 में विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ोतरी महज दो फीसदी रहने का अनुमान है जो 2005-06 के बाद सबसे कम है। इससे मौजूदा औद्योगिक सुस्ती करीब दो दशक में सबसे बदतर होगी। इसी तरह चालू वित्त वर्ष में निवेश की वृद्धि दर भी 0.97 फीसदी रहने का अनुमान है जो 15 साल में सबसे कम है। 2019-20 की दूसरी छमाही में सकल स्थिर पूंजी सृजन के संदर्भ में निवेश में 0.5 फीसदी की कमी आने की आशंका है जो दो दशक में सबसे बड़ी गिरावट होगी। अर्थव्यवस्था में निवेश की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। दो दशक पहले अर्थव्यवस्था में इसकी एक तिहाई हिस्सेदारी थी जो अब एक चौथाई रह गई है। निवेश दर भी 28.1 फीसदी रहने का अनुमान है जो 2004-05 के बाद सबसे कम है।

औद्योगिक और निवेश वृद्धि में वित्तीय संकट के साल भी इतनी गिरावट नहीं आई थी और बाद के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक जिसों की कीमतों और वित्तीय प्रवाहों का जोखिम बढ़ गया। इससे आने वाले वर्षों खासकर वित्त वर्ष 2021 में आर्थिक विकास और रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

नॉमिनल संदर्भ में भारत की जीडीपी के 7.5 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है जो कई दशकों का न्यूनतम स्तर है। इससे साफ है कि कर राजस्व और व्यक्तिगत आय पर आगे भी दबाव रहेगा। सेवा गतिविधियों के चालू वित्त वर्ष के दौरान 6.8 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और यह 5 फीसदी से नीचे जाने से बच जाएगी। वित्त वर्ष 2018 में सेवा गतिविधियों में 8.1 फीसदी और वित्त वर्ष 2019 में 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह इस वित्त वर्ष इसमें में गिरावट का अनुमान है।

चूंकि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के आंकड़े आ चुके हैं, इसलिए वार्षिक अनुमान दूसरी तिमाही में आर्थिक प्रदर्शन की थाह देते हैं।

इस वित्त वर्ष में अक्टूबर-मार्च अवधि में निजी उपभोक्ता खर्च के 7.3 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि पहली छमाही में यह महज 4 फीसदी रही थी। लेकिन इस दौरान सरकारी खर्च के गिरावट के साथ 8.5 फीसदी रहने का अनुमान है। सालाना आधार पर उपभोक्ता खर्च के 5.8 फीसदी और सरकारी खर्च के 10.5 फीसदी बढ़ने का अनुमान है।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 4 पर

अर्थव्यवस्था में नरमी

■ वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)
■ नॉमिनल जीडीपी वृद्धि

	वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	नॉमिनल जीडीपी वृद्धि
2018-19 पीई	6.8	11.2
2019-20 एई	5.0	7.5

अजय मोहंती

सेवा क्षेत्र से मिला सहारा, निर्माण क्षेत्र में नरमी बरकरार
सकल मूल्यवर्द्धन में वृद्धि, % सालाना आधार पर

	2018-19 पीई	2019-20 एई
कृषि क्षेत्र	2.9	2.8
विनिर्माण क्षेत्र	6.9	6.8
सेवा क्षेत्र	7.5	6.8
निर्माण क्षेत्र	7.5	6.8

निवेश में कमी, सरकारी व्यय की रफ्तार भी हुई कम
वृद्धि % में

	पहली छमाही	दूसरी छमाही
सार्वजनिक व्यय	12.3	8.5
निजी उपभोक्ता का व्यय	4.1	7.3
निवेश	2.5	-0.5

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एई : पहला अग्रिम अनुमान, पीई : अंतरिम अनुमान

बैंकों पर भारी पड़ेगा फंसा कर्ज

अभिजित लेले और देव चटर्जी
मुंबई, 7 जनवरी

फंसे ऋणों का मुद्दा नहीं सुलझने की स्थिति में बैंकों को मार्च 2020 तिमाही में अतिरिक्त 20 प्रतिशत रकम का प्रावधान करना पड़ सकता है। गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर 7 जून को आए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र में फंसे ऋणों के समाधान की समय सीमा 7 जनवरी को समाप्त हो गई है। बैंकरों ने कहा कि वे दिवालिया न्यायालयों से इतर समाधान पर ध्यान दे रहे हैं और उम्मीद है कि जनवरी अंत तक बिजली क्षेत्र के कुछ फंसे ऋण सुलझ जाएंगे। बैंकों का कहना है कि इससे उन्हें इस तिमाही में प्रावधान नहीं करने होंगे।

बैंकों ने फंसे ऋणों का अंबार खत्म करने के लिए आरबीआई से कुछ और समय मांगा है। बिजली कंपनियों में बैंकों के करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये फंसे हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का सबसे अधिक 57,000 करोड़ रुपये फंसा है और शेष रकम विभिन्न बैंकों ने दिए हैं। एसबीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केवल 20 प्रतिशत ही अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं, जो समाधान योजना लागू होने के बाद दोबारा अपने खाते में जोड़े जा सकते हैं। अधिकारी ने कहा,'फिलहाल हमें यह देखना है कि कितने मामलों के लिए हमारे पास टिकाऊ समाधान योजनाएं उपलब्ध हैं। इन मामलों के लिए बैंक अंतर-कर्जदाता समझौता(आईसीए) कर सकते हैं और मार्च 2020 से पहले योजना का क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में 20 प्रतिशत प्रावधान कर सकते हैं।'

बैंकों ने अतिरिक्त समय के लिए आरबीआई में अपना प्रतिनिधिमंडल भी भेजा है। आईएलऐंडएफएस और दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) जैसे कई बड़े मामले राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में विचाराधीन हैं। एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि रतनइंडिया पावर, प्रयागराज पावर और अंवता का झाबुआ पावर जैसे मामलों का समाधान जनवरी से पहले कर पाएंगे। अधिकारी ने कहा कि फंसे ऋण खातों से मुक्ति पाने के लिए बैंकों को कम से कम नौ से दस महीने का समय चाहिए।

आबीआई ने पिछले साल 7 जून को अपने परिपत्र में ऋण समाधान योजना के लिए 210 दिनों का समय दिया था। इस समय सीमा का अनुपालन नहीं करने पर बैंकों को संबंधित कंपनी को दीवालिया न्यायालय भेजना होगा या 20 प्रतिशत अतिरिक्त रकम का प्रावधान करना होगा। इसके साथ ही उन्हें ऋण शोधन एवं दीवालिया संहिता (आईबीसी) से बाहर समाधान खोजना होगा। औसतन बैंक दिवालिया न्यायालयों के माध्यम से 50 प्रतिशत से भी कम रकम वसूल पा रहे हैं और इसमें भी उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इन कारणों से बैंक न्यायालयों से इतर ऋण समाधन योजना तलाश रहे हैं। *(साथ में सुब्रत पांडा)*

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 2 पर

होगी मुश्किल

- बैंक बड़ी संख्या में फंसे ऋणों का समाधान करने में नाकाम
- जनवरी अंत तक कुछ बिजली कंपनियों के मामलों के निकल सकते हैं हल
- फंसे ऋण के समाधान के लिए बैंक चाहते हैं अतिरिक्त समय
- अब सारा दारोमदार आरबीआई पर

खस्ताहाल निजी बैंकों की नीलामी की योजना

सोमेश झा
नई दिल्ली, 7 जनवरी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लंबे समय से खराब वित्तीय स्थिति से जूझ रहे निजी क्षेत्र के बैंकों की नीलामी की योजना बना रहा है। केंद्रीय बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत सरकारी और निजी बैंकों के लिए अलग-अलग नियामकीय व्यवस्था अपनाना चाहता है। निजी बैंकों की नीलामी इसी योजना का हिस्सा है। आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि बैंक नियामक पीसीए में शामिल निजी बैंकों के लिए को जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकालने की व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है। इसी के तहत बैंकों की नीलामी की संभावना तलाशी जा रहा है।

सूत्र ने कहा, 'निजी बैंक हमेशा के लिए पीसीए ढांचे में नहीं रह सकते हैं। अगर प्रवर्तक लंबे समय तक बैंक को पटरी पर लाने में नाकाम रहते हैं तो आरबीआई ऐसे बैंकों की परिसंपत्तियों, देनदारियों और परिचालन को नीलाम कर सकता है। इसके लिए एक योजना तैयार की जा रही है।' अब तक आरबीआई ने विलय के जरिये निजी बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति को दुरुस्त करने के लिए हस्तक्षेप किया है। आरबीआई ने अंतिम बार सितंबर, 2006 में ऐसा हस्तक्षेप किया था। यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक (यूडब्ल्यूबी) के बदतर पूंजी आधार के कारण केंद्रीय बैंक ने उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 17 संस्थाओं ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी और आरबीआई ने यूडब्ल्यूबी के कामकाज पर एक महीने की पाबंदी लगाने के बाद उसका आईडीबीआई में विलय करने का फैसला किया था। 2004 से पहले आरबीआई निजी क्षेत्र के ग्लोबल ट्रस्ट बैंक पर तीन महीने की रोक लगाने के बाद उसका सार्वजनिक क्षेत्र के ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में विलय कर दिया था। अलबत्ता, उसने अब तक किसी कमजोर बैंक की नीलामी नहीं की है।

सलाहकार फर्म अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख ने कहा, 'आरबीआई को मौजूदा कानून के तहत ऐसा करने का अधिकार है। पहले आरबीआई विलय के जरिये निजी बैंकों की नाजुक वित्तीय स्थिति का समाधान करता था। लेकिन इसमें बैंकों की नीलामी की योजना शामिल नहीं थी। यह आरबीआई का एक प्रगतिशील दृष्टिकोण लगता है क्योंकि नीलामी के जरिये नाकाम बैंक के शेयरधारकों को अपने निवेश का बेहतर मूल्य मिलेगा। यह व्यवस्था के लिए अच्छा है।' अमेरिका में स्वतंत्र एजेंसी द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बैंकों के समाधान का अधिकार है और वह नाजुक स्थिति से गुजर रहे वित्तीय संस्थानों की मजबूत बैंकों को नीलामी करता है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

नीलाम होंगे बीमार निजी बैंक!

- अभी निजी और सरकारी बैंकों के लिए पीसीए के समान नियम
- एनपीए, पूंजी पर्याप्तता की सीमा का उल्लंघन पर बैंकों को पीसीए में रखा जाता है
- अभी छह बैंक पीसीए में, इनमें से दो निजी क्षेत्र के

दुबई की तर्ज पर देश में शुरू होंगे शॉपिंग फेस्टिवल : सीतारमण

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी

- छोटे-मझोले शहरों में आयोजित होंगे मेगा शॉपिंग फेस्टिवल
- जीएसटी को और सरल बनाने का दिया भरोसा

भारत में भी जल्द ही दुबई की तर्ज पर मेगा शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो सकती है। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस तरह के फेस्टिवल छोटे-मझोले शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को और सरल बनाने का भरोसा दिया।

सीतारमन ने कहा कि बजट में दुबई की तरह देश में मेगा शॉपिंग फेस्टिव आयोजित करने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत जल्द ही छोटे-मझोले शहरों में बड़े पैमाने पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप आपूर्ति के लिए तो बहुत कुछ कर रही है लेकिन मांग बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है ? इस पर मेरा कहना है कि मांग बढ़ाने के लिए लोगों की जेब में सीधे पैसा पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में इन शॉपिंग फेस्टिवल के माध्यम से कारोबारियों को विपणन की सुविधा मिलेगी।

वित्त मंत्री ने कारोबारियों की जीएसटी संबंधी दिक्कतों, जैसे कि रिटर्न भरने में परेशानी, आईटीसी बंदिश के साथ ही आयकर के नोटिस, ई-कॉमर्स से परेशानी आदि पर कहा कि सरकार जीएसटी को और सरल बनाने लिए सभी हितधारकों से राय लेकर लगातार काम कर रही है। आज ही राजस्व सचिव ने 12 देशों के जीएसटी अधिकारी समेत अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। इस बैठक में पिछले महीने हितधारकों से लिए गए सुझावों पर चर्चा हुई। सरकार इन सुझावों के आधार पर जीएसटी को सरल बनाएगी। उन्होंने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भी उन्हें और राहत दी जाएगी। आगामी आम बजट भी कारोबारियों के लिए राहत भरा होगा।

सैमसंग ने उठाया कृत्रिम मानव से पर्दा

विभु रंजन मिश्रा
बेंगलूरु, 7 जनवरी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की दुनिया में चैट बोट्स और सिरी तथा एलेक्सा जैसे पर्सनल असिस्टेंट्स के बाद तकनीकी क्षेत्र के दिग्गज अब कृत्रिम मानव बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। हालांकि इस योजना को साकार होने में कुछ समय या शायद कुछ साल तक इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की दिग्गज सैमसंग स्टार लैब्स जाने-माने कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री की अगुआई में इस क्षेत्र में कुछ अहम प्रगति हासिल की है। अब तक गुपचुप तरीके से काम कर रहे लैब्स ने अमेरिका के लास वेगस में हो रहे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में आज दुनिया के पहले 'कृत्रिम मानव' की झलक पेश की। लैब्स ने इसे निऑन नाम दिया है।

निऑन - निओ (नया) और ह्यमैन (मानव) शब्द को मिलाकर बनाया गया है। लैब्स का दावा है कि यह कंप्यूटरीकृत कृत्रिम मानव है, जो दिखने और व्यवहार में एकदम असली मानव की तरह है। यह भावनाएं प्रकट कर सकता है और वास्तविक मनुष्य की तरह बुद्धिमानी और हमदर्दी जता सकता है। निऑन लक्ष्य-केंद्रित कामों में मदद कर सकता है और इसे उन कामों में मदद के लिए तैयार किया जा सकता है जिसमें मानवीय संवेदनाओं की जरूरत होती है, जैसे कि शिक्षक, वित्तीय सलाहकार, अभिनेता, वक्ता या टेलीविजन के एंकर। इस परियोजना के पीछे स्टार लैब्स के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी मिस्त्री का दिमाग है। मिस्त्री ने स्पष्ट किया कि निऑन के उत्पादन में अभी वक्त लगेगा क्योंकि लैब्स कुछ मुख्य प्रौद्योगिकी को तैयार करने में जुटा है। सिक्स्थ सेंस और सैमसंग ग्लैक्सी गियर जैसी अत्याधुनिक तकनीक के जनक मिस्त्री ने कहा, 'हम इस तकनीक पर लंबे समय से काम कर रहे हैं और दुनिया को इसकी झलक पेश करने के लिए सही समय से पहले हम इसे अपने तक सीमित रखना चाहते थे।' उन्होंने कहा, 'इसके पूरी तरह से तैयार होने में कुछ वर्ष या दशक भी लग सकते हैं। हम इसे लेकर इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि इसमें कई दिलचस्प चीजें शामिल होंगी जो निऑन को एकदम अलहदा बनाएगा।' (शेष पृष्ठ 12 पर)

अमेरिका के लास वेगस में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में सैमसंग स्टार लैब ने दिखाई कृत्रिम मानव की झलक।

तकनीक की उड़ान

- सैमसंग स्टार लैब्स के प्रणव मिस्त्री की अगुआई में तैयार किया निऑन
- मानवीय भावनाओं को समझने में समक्ष होगा निऑन
- दिखने और बात करने में वास्तविक मनुष्य की तरह होगा निऑन
- साल के अंत तक हो सकता है इसके बीटा संस्करण का परीक्षण
- अगले चरण में इसे और उन्नत तकनीक से लैस करने की तैयारी कर रही सैमसंग स्टार लैब्स

खबरों में रहे स्टॉक

आईटीआई

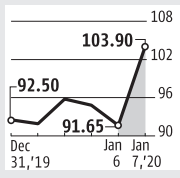

तीसरी तिमाही में मुनाफा बढ़कर 168 करोड़ रुपये पर पहुंचा

₹ 91.65 पिछला बंद भाव
₹ 103.90 आज का बंद भाव
▲ 13.37 %

श्री सीमेंट

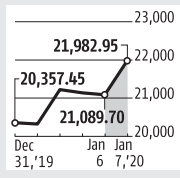

एसऐंडपी बीएसई 100 के शेयरों में सबसे ज्यादा चढ़ा

₹ 21,089.70 पिछला बंद भाव
₹ 21,982.95 आज का बंद भाव
▲ 4.24 %

सेंट्रम कैपिटल

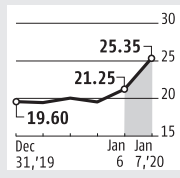

गिरवी प्रवर्तक हिस्सेदारी 64.43 फीसदी से घटकर 38.89 फीसदी रही

₹ 21.25 पिछला बंद भाव
₹ 25.35 आज का बंद भाव
▲ 19.29 %

डिक्सन टेक्नोलॉजिज

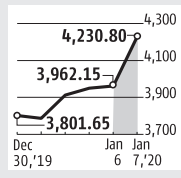

एलईडी टीवी बनाने के लिए सैमसंग संग साझेदारी

₹ 3,962.15 पिछला बंद भाव
₹ 4,230.80 आज का बंद भाव
▲ 6.78 %

बीपीसीएल

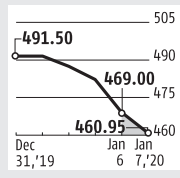

चार दिन में 6 फीसदी टूटा शेयर, बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ के नीचे

₹ 469.00 पिछला बंद भाव
₹ 460.95 आज का बंद भाव
▼ 1.72 %

संक्षेप में

मण्णपुरम फाइनैंस ने जुटाए 30 करोड़ डॉलर

मण्णपुरम फाइनैंस ने आज कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय बाजार से 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,100 रुपये) जुटाए हैं। इस रकम का इस्तेमाल ऋण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा। *एजेंसी*

737 मैक्स पर नहीं घट रहीं बोइंग की उलझनें

बोइंग को अपने 737 विमानों में सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या कमी दूर करनी पड़ सकती है, इसकी सूची बढ़ती जा रही है। इसमें विमान की नियंत्रण प्रणालियों के तारों के संयोजन की समस्या भी जुड़ गई है। इसके अलावा सोमवार को इन विमानों को खड़े किए जाने से बोइंग के वित्तीय नुकसान का मुद्दा भी उभर कर सामने आया। *भाषा*

विद्युत क्षेत्र में फंसी संपत्तियां

सात का समाधान, दो दर्जन अधर में

श्रेया जय
नई दिल्ली, 7 जनवरी

लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य के सर्वाधिक एनपीए (गैर-निष्पादित आस्तियां) वाले विद्युत उत्पादन क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नरम मानकों के बाद भी चालू वित्त वर्ष में कम सफलता हाथ लगने की संभावना दिख रही है। एनपीए के समाधान से संबंधित आरबीआई की आखिरी समय-सीमा 7 जनवरी बीत जाने के बाद भी लगभग दो दर्जन परिसंपत्तियां अनुकूल ऋण पुनर्गठन की राह देख रही हैं।

हालांकि लगभग 9-12 मामलों के लिए उम्मीद की किरण दिख रही है। उनका प्रमुख ऋणदाता पावर फाइनैंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) है, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और उसे आरबीआई की इस समय-सीमा से छूट हासिल है। वहीं बैंकों के लिए यह समय-सीमा अनिवार्य है।

विद्युत क्षेत्र में कर्ज की समस्या से जूझ रहीं कुल चिह्नित 36 परिसंपत्तियों में से सात का समाधान ऋणदाताओं द्वारा विभिन्न ऋण पुनर्गठन योजनाओं के जरिये निकाला जा चुका है। इनमें जेपी की प्रयागराज परियोजना भी शामिल है जिसे आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाटा पावर के संयुक्त उपक्रम द्वारा खरीदा गया था। इसके अलावा इनमें एनएचपीसी द्वारा खरीदी गई लैंको तीस्ता पनबिजली परियोजना और रत्तन इंडिया पावर की अमरावती विद्युत परियोजना (जिसे हाल में गोल्डमैन सैक्स के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को बेचा गया है) शामिल है।

- विद्युत क्षेत्र में एनपीए के तौर पर चिह्नित 36 परिसंपत्तियों में से सात का समाधान ऋणदाताओं द्वारा विभिन्न ऋण पुनर्गठन योजनाओं के जरिये निकाला जा चुका है
- पीएफसी ने चालू वित्त वर्ष में 14,704 करोड़ रुपये मूल्य की 15 परियोजनाएं एनसीएलटी को सौंपी

अदाणी पावर ने दो फंसी परिसंपत्तियों - जीएमआर की छत्तीसगढ़ विद्युत परियोजना और अवांता ग्रुप की कोरबा वेस्ट विद्युत परियोजना का अधिग्रहण किया है।

25 परियोजनाएं केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद अभी भी समाधान की राह तलाश रही हैं। इनमें से 14 को राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) में दिवालिया प्रक्रिया के लिए भेजा गया है। मौजूदा समय में चार परिसंपत्तियां एनसीएलटी से बाहर कर्ज समाधान की प्रक्रिया से गुजर रही हैं जिनमें जीएमआर कमालंगा, जीएमआर वरोरा, एस्सार टोरी और रत्तन इंडिया पावर नासिक शामिल हैं। जिन फंसी परियोजनाओं का समाधान नहीं निकला है, उनमें 11,000 मेगावॉट क्षमता की करीब 10 परिसंपत्तियां शामिल हैं, जो अधूरी हैं और उन्हें कोई खरीदार मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। पीएफसी ने चालू वित्त वर्ष में 14,704 करोड़ रुपये मूल्य की 15 परियोजनाएं एनसीएलटी को सौंपी हैं। साथ ही अन्य ऋणदाताओं के साथ 14,762 करोड़ रुपये मूल्य की 14 परिसंपत्तियों के लिए एनसीएलटी के बाहर भी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। पीएफसी ने 2019-20 के दौरान बकाया ऋणों के लिए अपने बहीखाते में 16,275 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल किया। एक ऋणदाता की सितंबर 2019 की निवेशक रिपोर्ट में कहा गया, 'पीएफसी को जनवरी 2020 तक चार परियोजनाओं जून तक एक अन्य परियोजना का समाधान निकलने का अनुमान है। 9 परियोजनाएं 2,629 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ी हुई हैं, जो आरबीआई के सर्कुलर से प्रभावित नहीं होंगी।' ये वे परियोजनाएं हैं जिनमें पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है।

परिसमापन प्रक्रिया से प्रतिबंधित रहेंगी अयोग्य कंपनियां

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 7 जनवरी

भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दिवालिया समाधान में हिस्सा लेने से अयोग्य करार दिए गए प्रवर्तक या संबंधित कंपनियों पर अब परिसमापन प्रक्रिया में शामिल होने पर भी प्रतिबंध होगा।

आईबीबीआई ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग कंपनी ऐक्ट की धारा 230 के तहत दिवालिया कंपनी के लेनदारों के साथ कोई समझौता करने के हकदार भी नहीं होंगे। लिक्वडेशन प्रोसेस-एमेंडमेंट रेग्युलेशंस, 2020 के लिए यह अधिसूचना 6 जनवरी 2020 से प्रभावी है।

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) ने इरादतन चूक से जुड़े प्रवर्तकों को अपनी कंपनी का नियंत्रण लेने से रोकने के लिए धारा 29ए पेश की थी।

आईबीबीआई ने परिसमापन प्रक्रिया के नियमों में संशोधन कर यह पाबंदी लागू की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंगलवार को कहा गया कि सिक्योर (सुरक्षित) कर्जदाता को दिवाला समाधान और परिसमापन प्रक्रिया की लागत में अपने हिस्से का योगदान तथा कर्मचारियों के बकाये का भुगतान परिसमापन शुरू होने की तारीख से 90 दिन के भीतर देना होगा।

आईबीसी में ऋण संकट में फंसी कंपनियों के लिए समाधान प्रक्रिया के नियम तय हैं। यदि समाधान प्रक्रिया परवान नहीं चढ़ पाती है तो उस स्थिति में कंपनी का परिसमापन किया जाता है। विज्ञप्ति में कहा गया है, 'कोई ऐसा व्यक्ति, जो कर्जदार कंपनी के लिए दिवाला समाधान के लिए प्रस्ताव रखने का पात्र नहीं है, उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के तहत कर्जदार कंपनी के साथ समझौते या व्यवस्था में किसी भी तरह से पक्ष नहीं बनाया जाएगा। सुरक्षित कर्जदाता को परिसंपत्ति के लिए दावे से ज्यादा वसूली होने की स्थिति में बढ़ी हुई राशि का भुगतान परिसमापन शुरू होने की तारीख से 180 दिन के भीतर करना होगा।'

- 29ए के तहत अयोग्य घोषित पक्ष परिसमापन प्रक्रिया में नहीं ले सकेगा हिस्सा

कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स में पार्टनर मनोज कुमार ने कहा, 'नियमों में संशोधन के जरिये आईबीबीआई ने व्यवसाय में फिर से आने को इच्छुक कई प्रवर्तकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लेकिन क्या ये प्रावधान कंपनीज ऐक्ट का दायरा सीमित कर सकते हैं, यह एक प्रमुख विषय है।'

अक्टूबर, 2019 में एनसीएलएटी ने गुजरात एनआरई कोक के मामले में फैसला दिया था कि अयोग्य प्रवर्तक कंपनीज ऐक्ट के तहत स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिये पुन: नियंत्रण हासिल नहीं कर सकते हैं।

सिमैनटक का साइबर सुरक्षा सेवा कारोबार खरीदेगी एक्सेंचर

एक्सेंचर ने मंगलवार को कहा कि वह सिमैनटक का साइबर सुरक्षा सेवा कारोबार ब्रॉडकॉम से खरीदेगी, लेकिन इस सौदे की कीमत का खुलासा कंपनी ने नहीं किया।यह अधिग्रहण एक्सेंचर को प्रबंधित सुरक्षा सेवा में अग्रणी सेवा प्रदाताओं में से एक बना देगा और इससे एक्सेंचर साइबर खतरे का अनुमान लगाने, उसका पता लगाने और उस पर प्रतिक्रिया देने में कंपनियों को मदद की अपनी क्षमता में बढ़ोतरी कर लेगी।

साइबर सुरक्षा सेवा के सिमैनटक के पोर्टफोलियो में वैश्विक स्तर पर निगरानी व विश्लेषण शामिल है, जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के नेटवर्क के जरिए होता है।कंपनी के छह सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान में हैं। इसके प्रबंधित सुरक्षा सेवा कारोबार को प्रोप्राइटरी क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म से समर्थन मिलता है। एक्सेंचर की मुख्य कार्याधिकारी जूली स्वीट ने एक बयान में कहा, साइबर सुरक्षा हर संगठन के लिए अहम कारोबारी अनिवार्यताओं में एक बन गया है, चाहे कोई भी उद्योग है या किसी भी इलाके में वह अवस्थित हो। *बीएस*

नए मार्जिन मानकों से छोटे शेयरों पर पड़ सकता है दबाव

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 7 जनवरी

कारोबार पर नए मानकों से मिड-कैप, स्मॉल-कैप और चवन्नी शेयरों पर दबाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि पिछले सप्ताह एक्सचेंजों द्वारा मार्जिन के संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद इनके लिए जरूरी मार्जिन बढ़ने का अनुमान है। पिछले सप्ताह जारी सूचना के अनुसार शेयर ब्रोकरों को अपने ग्राहकों से अग्रिम तौर पर (कैश और डेरिवेटिव, दोनों में) मार्जिन जुटाना होगा।

एक वरिष्ठ शेयर ब्रोकर ने कहा, 'कृत्रिम रूप से बिक्री तैयार करने के लिए डीलरों द्वारा छोटी कंपनियों, खासकर चवन्नी शेयरों में कारोबार देखा गया, क्योंकि अपफ्रंट मार्जिन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस कारोबार में गिरावट आएगी।' उनके अनुसार अब ग्राहकों को एक्सचेंज की गणनाओं पर आधारित मार्जिन चुकाने की जरूरत होगी।

विश्लेषकों का मानना है कि तेजी से जुड़े 90 प्रतिशत से ज्यादा चवन्नी शेयरों पर उन ऑपरेटरों की नजर रहती है जो इन कंपनियों के प्रवर्तकों द्वारा दी गई पूंजी का

इस्तेमाल करते हैं, न कि किसी मौलिक कारण के लिए। पिछले सप्ताह जारी एक एक्सचेंज गणना के अनुसार, कैश सेगमेंट के लिए, वैल्यू-एट-रिस्क (वीएआर) मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन (ईएलएम) कारोबार के अग्रिम तौर पर जुटाना होगा और अन्य मार्जिन स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा मार्जिन कॉल के बाद जुटाया जाएगा। वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) सेगमेंट में अब सदस्यों को ग्राहकों से अग्रिम तौर पर शुरुआती मार्जिन, नेट बाई प्रीमियम, डिलिवरी मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन लेना अनिवार्य है। प्रभुदास लीलाधर में रिटेल ब्रोकिंग के प्रमुख संदीप राइचुरा ने कहा, 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 400-500 शेयरों से ज्यादा के लिए उधारी नहीं दे रही हैं। अब अतिरिक्त मार्जिन जरूरत ब्रोकरों को उधारी के संबंध में मिली रियायत समाप्त कर देगी। इससे खासकर मिड- और स्मॉल-कैप शेयर प्रभावित हो सकते हैं।' राइचुरा का कहना है, 'हालांकि यह पहल दीर्घावधि में फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन अल्पावधि में हम इसमें समस्याएं देख सकते हैं।'

नियामक द्वारा म्युचुअल फंडों के लिए इन शेयरों के वर्गीकरण के बाद मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट पर दबाव पड़ा है। शुरू में शेयरों को लार्ज-, मिड-, या स्मॉल-कैप के तौर पर वर्गीकृत करने के लिए कोई मानक परिभाषा नहीं थी। सेबी द्वारा इन शेयरों को बाजार पूंजीकरण के आधार पर वर्गीकृत किए जाने के बाद यह बदलाव आया। बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में प्रमुख-100 कंपनियों को लार्ज-कैप के तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया है, 101 से 250 की रैंकिंग वाली कंपनियां मिड-कैप, और 251 से ऊपर की स्मॉल-कैप हैं। जीरोधा के मुख्य कार्याधिकारी नितिन कामत ने कहा है, 'सर्कुलरों में कहा गया है कि पूरा शुरुआती मार्जिन व्यापार से पहले अग्रिम तौर पर जुटाने की जरूरत होगी, भले ही यह दिन के कारोबार से संबंधित हो।'

दूरसंचार राजस्व 50,000 करोड़ रुपये ज्यादा रहने के आसार

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 7 जनवरी

वर्ष 2019-20 के लिए सरकार दूरसंचार क्षेत्र से राजस्व के लिए अपने बजटीय लक्ष्य में 13,000 करोड़ रुपये और 50,000 करोड़ रुपये के बीच इजाफा दर्ज कर सकती है। राजस्व में यह वृद्धि सर्वोच्च न्यायालय के पास समीक्षा याचिका पर निर्भर करेगा, जिसमें लाइसेंस शुल्कों और स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता इस्तेमाल (एसयूसी) के तौर पर दूरसंचार कंपनियों से 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया चुकाने को कहा गया है।

अपने जुलाई के बजट में सरकार ने 2019-20 में दूरसंचार क्षेत्र से 50,519 करोड़ रुपये हासिल होने का लक्ष्य रखा था जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि है और इसे मुख्य रूप से लाइसेंस शुल्क, एसयूसी, और खरीदे गए स्पेक्ट्रम से संबंधित रकम शामिल होगी।

अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित बनाए रखने के लिए सरकार को धन जुटाना बेहद जरूरी है। इसका स्पष्ट संकेत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से गैर-कर राजस्व के लिए सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा, लेकिन अब तक वह

सिर्फ 17,364 करोड़ रुपये जुटाने में ही सफल रही है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और एयर इंडिया के इस साल विनिवेश सूची से अलग रहने से यह लक्ष्य हासिल होने योग्य नहीं दिख रहा है। विनिवेश योजना में विलंब ऐसे समय में हुआ है जब सरकार का राजकोषीय घाटा नवंबर में वित्त वर्ष 2020 के बजट अनुमान के 115 प्रतिशत को छू चुका है। दूरसंचार क्षेत्र से और भी उम्मीदें हैं। मौजूदा अनुमानों के आधार पर, सरकार को वित्त वर्ष 2020 के लिए विलंब से संबंधित स्पेक्ट्रम भुगतान के तौर पर 21,444 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। हालांकि इस राजस्व पर विपरीत प्रभाव अगले वित्त वर्ष (2020-21) में महसूस किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर दूरसंचार कंपनियों को इस भुगतान के संबंध में अगले दो वित्त वर्षों की मोहलत दी है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के अनुमानों के अनुसार, उद्योग द्वारा लाइसेंस शुल्क और एसयूसी के तौर पर इस वित्त वर्ष में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने की संभावना है। शुरुआती तिमाहियों में सपाट राजस्व वृद्धि के बाद आखिरी दो तिमाहियों में इसमें तेजी आ सकती है, क्योंकि दूरसंचार कंपनियों ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी दरों में 15-40 प्रतिशत तक का इजाफा किया।

योजनाओं के वर्गीकरण के नियम बदलेगा सेबी

पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीला रुख चाहते हैं फंड मैनेजर

जश कृपलानी
मुंबई, 7 जनवरी

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) योजनाओं के वर्गीकरण के नियम में बदलाव पर विचार कर रहा है ताकि इक्विटी फंड मैनेजरों को लार्ज और मिडकैप फंड पोर्टफोलियो के प्रबंधन में और लचीला रुख अपनाने की अनुमति दी जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, फंड कंपनियों ने बाजार नियामक सेबी से संपर्क कर लार्जकैप व मिडकैप शेयरों के मौजूदा वर्गीकरण का दायरा बढ़ाने की मांग की है। एक फंड हाउस के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, सेबी इन चुनौतियों को समझने के लिए म्युचुअल फंडों से संपर्क कर रहा है। जिससे कि म्युचुअल फंडों के लिए हर छह महीने में जारी शेयरों की अद्यतन सूची के मुताबिक अनावश्यक बदलाव सीमित हो जाए।

मौजूदा नियम के तहत बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 100 अग्रणी कंपनियां लार्जकैप में शामिल होती है और अगली 150 कंपनियां मिडकैप के दायरे में आती हैं जबकि बाकी स्मॉलकैप श्रेणी में मानी जाती हैं। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया हर छह महीने में इन तीनों श्रेणियों के लिए शेयरों की सूची तैयार करती है, जैसा कि नियामक ने पारिभाषित किया है।

म्युचुअल फंडों के अधिकारियों ने सेबी से एक ऐसा ढांचा अपनाने का अनुरोध किया है जो कुल बाजार पूंजीकरण में कंपनी के योगदान पर ध्यान दे, न कि लार्जकैप व मिडकैप के दायरे वाली कंपनियों के लिए तय विशिष्ट मानकों से चिपके रहा जाए। अधिकारी ने कहा, इससे बाजार को रैंकिंग आधारित व्यवस्था से आगे विस्तार की अनुमति मिलेगी, जो कंपनियों की विशिष्ट संख्या से बंधी हुई है।

अक्टूबर 2017 में सेबी ने योजनाओं के वर्गीकरण का नियम तय किया था, जो यह सुनिश्चित करने के लिए था कि म्युचुअल फंडों की योजनाएं अपनी योजनाओं के लिखित स्वरूप के मुताबिक निवेश करे।

लार्ज-कैप सूची से हाल में बाहर हुए शेयर

कंपनी	औसत 6 महीने का बाजार पूंजीकरण
येस बैंक	16,179
इंडियाबुल्स	16,626
वोडाफोन आइडिया	18,896
न्यू इंडिया एश्योरेंस	21,251
कैडिला हेल्थकेयर	24,548

स्रोतः एम्फी की ताजा बाजार पूंजीकरण समीक्षा
आंकड़ेः करोड़ रुपये में

येस बैंक, वोडाफोन लार्जकैप से बाहर

येस बैंक और वोडाफोन आइडिया, लार्जकैप म्युचुअल फंड योजनाओं के बिकवाली के दबाव में आ सकते हैं क्योंकि इन शेयरों को एम्फी ने अपनी हालिया अद्यतन सूची में लार्जकैप की सूची से बाहर कर दिया है। एम्फी हर छह महीने में औसत बाजार पूंजीकरण के आधार पर कंपनियों की रैंकिंग करता है। लार्जकैप की सूची से बाहर निकलने वाले अन्य शेयर हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग, न्यू इंडिया एश्योरेंस और कैडिला हेल्थकेयर। म्युचुअल फंडों को नए वर्गीकरण के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करना होगा।

खस्ताहाल निजी बैंकों की नीलामी की रिजर्व बैंक की योजना

पृष्ठ-1 का शेष

भारत में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों (सरकारी और निजी) की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए पीसीए को शुरुआती चेतावनी के हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर कोई बैंक पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे पीसीए में डाला जाता है। यह व्यवस्था 2002 से चलन में है और 2017 में आरबीआई ने इसे ज्यादा सख्त बनाया था। इसके तहत कमजोर बैंकों के विस्तार, लाभांश वितरण और प्रबंधन को मिलने वाले मुआवजे पर पाबंदी लगा दी गई। केंद्रीय बैंक 2020 में पीसीए व्यवस्था की समीक्षा करेगा। अभी छह बैंक पीसीए में शामिल हैं जिनमें निजी क्षेत्र के दो बैंक आईडीबीआई बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक शामिल हैं। आईडीबीआई बैंक को मई 2017 में और लक्ष्मी विलास बैंक को सितंबर 2019 में इसमें शामिल किया गया था। एक साल पहले 12 बैंक इसमें शामिल थे जिनमें 11 सरकारी और एक निजी बैंक था।

अभी बैंकों को पीसीए से बाहर निकालने के लिए कोई तय व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक साल से आरबीआई उन बैंकों पर से पीसीए पाबंदियां हटा रहा है जो पीसीए की सीमाओं के दायरे में आ गए हैं।

ब्लैकस्टोन की नई रिपोर्ट में पहली बार भारत को अहमियत

साल 2020 के लिए 10 आश्चर्य शीर्षक से जारी रिपोर्ट में भारत में रिकवरी पर दांव

पवन लाल
मुंबई, 7 जनवरी

प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन के वाइस चेयरमैन बायरॉन वियेन और मुख्य निवेश रणनीतिकार जो जिडल की तरफ से तैयार सालाना वैश्विक बाजार की रिपोर्ट में तीन दशक से ज्यादा समय के बाद पहली बार भारत का जिक्र किया गया है।

साल 2020 के लिए 10 आश्चर्य शीर्षक से जारी रिपोर्ट में अनिवार्य तौर पर अप्रत्याशित घटनाक्रमों की सूची है, जो इस साल दुनिया भर में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर असर डाल सकते हैं।

विशेष रूप से हालिया प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में आर्थिक संकट को लेकर भय कम हुआ है। उभरते बाजारों का प्रदर्शन विषम बना हुआ है, लेकिन भारत में सुधार हो रहा है।

मोदी सरकार कारोबार के अनुकूल बढ़त के लिए सुधार जारी रखे हुए है और अर्थव्यवस्था 6 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है और बाजार में 20 फीसदी की उछाल आई है।

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टॉप-10 में क्या शामिल है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनुमान से कम रह सकती है, लेकिन मंदी में भी नहीं फंसेगी। साथ ही बढ़ती असमानता और जलवायु परिवर्तन चुनाव के अहम मुद्दे होंगे और यह भी कि महाभियोग की कार्यवाही के बावजूद व्हाइट हाउस में ट्रंप दृढ़ता से जमे हुए हैं, जो उन्हें बाहर निकालने में नाकाम रहा। बौद्धिक संपदा अधिग्रहीत करने की चीन की क्षमता को सीमित करने वाले दो कारोबारी समझौते और स्वचालित कार की वास्तविकता भविष्य के गर्त में चली गई है।

मुथूट फाइनैंस के एमडी हमले में घायल

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मुथूट फाइनैंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज एलेक्जेंडर एक अज्ञात व्यक्ति के हमले से घायल हो गए। उस व्यक्ति ने एलेक्जेंडर की कार पर पत्थर फेंक दिया। उन्हें कोच्चि के मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, उनके सिर में चोट लगी है।

स्थानीय चैनल पर प्रसारित खबर के मुताबिक, एक व्यक्ति ने एक कार पर पत्थर फेंका, जिससे एलेक्जेंडर यात्रा कर रहे थे। यह ऐसे समय में हुआ जब सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस के सामने कंपनी के खिलाफ पिछले कुछ दिन से विरोध प्रदर्शन कर रही है।

आरोप है कि हमलावर विरोध प्रदर्शन करने वालों में से एक है जबकि सीटू ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि यह विरोध प्रदर्शन अहिंसक रहा है। बताया जाता है कि राज्य के श्रम मंत्री टी पी रामकृष्णन ने कहा है कि ट्रेड यूनियन के लोगों ने शायद यह हमला नहीं किया होगा।

मुथूट फाइनैंस ने पहले कहा था कि वह राज्य में अपनी मौजूदगी कम करने के लिए कदम उठाएगी और आरोप है कि गृह प्रदेश केरल में सीटू ने बलपूर्वक उसकी शाखाएं बंद कराई है। *बीएस*

मॉर्गन स्टैनली की 20 अग्रणी शेयरों की सूची में एकमात्र देसी फर्म मारुति

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 7 जनवरी

मॉर्गन स्टैनली सेल्स ऐंड ट्रेडिंग, अमेरिका ने मारुति सुजूकी इंडिया को दुनिया के 20 अग्रणी शेयरों में शामिल किया है। मॉर्गन स्टैनली की ट्रेडिंग इकाई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की अग्रणी कार कंपनी मांग में बढ़ोतरी के लिहाज से बेहतर स्थिति में है।

मॉर्गन स्टैनली की वैश्विक सूची में मारुति भारत की एकमात्र कंपनी के तौर पर शामिल हुई है। फर्म का मानना है कि यह शेयर अन्य के मुकाबले बेहतर स्थिति में है और इसमें 73 फीसदी तक बढ़त हो सकती है। अर्थव्यवस्था में मंदी ने मांग पर असर डाला है और इसकी वजह से वाहन बाजार में कुल खपत में गिरावट दर्ज हुई है, जो हाल तक दुनिया भर में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बाजार था।

यात्री वाहनों की बिक्री भारत में मौजूदा वित्त वर्ष के पहले आठ महीने में 16 फीसदी घटकर 18 लाख वाहन रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 22 लाख वाहन रही थी। यह जानकारी उद्योग संगठन सायम के आंकड़ों से मिली। इसकी वजह यह है कि कंपनियों ने मांग के हिसाब से उत्पादन के लिए डीलरों को कम वाहनों की आपूर्ति की। यात्री वाहनों की बिक्री में आधी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी मारुति ने साल दर साल के हिसाब से बिक्री में इस साल दिसंबर 2019 तक 12.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की है, जो एक दशक की सबसे खराब स्थिति है।

रिपोर्ट में कहा गया है, उद्योग गिरावट के लंबे चक्र का सामना कर रहा था और अब बढ़त के संकेत दिखा रहा है।

इसमें कहा गया है कि कंपनी कर घटाने के सरकारी कदम से पूंजीगत खर्च में सुधार होगा और जीडीपी की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे उपभोग में इजाफा होगा। मजबूत बाजार हिस्सेदारी और वितरण में विस्तृत मौजूदगी के कारण मारुति मांग में बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा फायदा उटाने वाली कंपनी बन सकती है। साथ ही कंपनी बीएस-6 वाहन में भी हिस्सेदारी हासिल करना जारी रखेगी और साल 2022 तक कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (कैफे) नियम की ओर बढ़ने में भी बेहतर कर सकती है।

लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। शेयरखान के विश्लेषक भारत ज्ञानी ने कहा, किया मोटर्स व एमजी मोटर्स जैसी नई कंपनी से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए बाजार हिस्सेदारी बनाए रखना मारुति के लिए आसान नहीं होगा। कंपनी पहले ही बाजार हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा, यह शेयर पहले से ही प्रीमियम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है और हम इसमें मौजूदा स्तर से बढ़त की सीमित गुंजाइश देख रहे हैं।

हड़ताल से बैंक सेवाएं हो सकती हैं बाधित : ट्रेड यूनियनों की बुधवार को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान बैंक सेवायें प्रभावित हो सकतीं हैं। देश की दस केंद्रीय मजदूर यूनियनों ने आठ जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। ज्यादातर बैंकों ने इस हड़ताल और इससे उनकी सेवाओं पर पड़ने वाले असर के बारे में शेयर बाजारों को सूचित कर दिया है। बैंक कर्मचारियों की ज्यादातर यूनियनों ने भी हड़ताल में भाग लेने और उसका समर्थन करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। *भाषा*

एयर इंडिया के टेंडर को सरकार की मंजूरी

बोलीकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सरकार उठाएगी ज्यादा कर्ज व देनदारियों का बोझ

अरिंदम मजूमदार और अनीश फडणीस
नई दिल्ली, 7 जनवरी

सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया में 100 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी बेचने को मंत्रियों के एक समूह ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने समूह ने एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसके लिए रुचि पत्र (ईओआई) और शेयर खरीद समझौते के लिए तैयार प्रारूप को मंजूरी दे दी।

बिक्री की प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से इसकी सार्वजनिक घोषणा दो सप्ताह के भीतर की जाएगी।

मंत्रिसमूह ने एयरलाइंस के कर्ज व देनदारियों के लिए अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये अलग रखने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो विशेष उद्देश्य इकाई के माध्यम से दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे संभावित खरीदारों के लिए एयर इंडिया और आकर्षक हो जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'समिति ने रुचि पत्र, शेयर खरीद समझौते व कर्ज को आगे और पुनर्गठित करने को आज मंजूरी दी है। बोलीकर्ताओं के लिए रुचि पत्र जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।'

यह तीसरा मौका है जब सरकार एयर इंडिया के निजीकरण की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने 2017 में इसे बेचने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। एयरलाइंस को खरीदने के लिए एक भी खरीदार सामने नहीं आया। एयर इंडिया के अंकेक्षित खाते के मुताबिक वित्त वर्ष 19 के आखिर में कंपनी पर 58,351 करोड़ रुपये कर्ज था। अगर एयर इंडिया को बेचने में सरकार सफल होती है तो उसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च करने को धन मिल सकेगा, क्योंकि वह वित्तीय दबाव में है। वित्त वर्ष 2018-19 में सराकर ने एयरलाइंस में करीब 30,000 करोड़ रुपये डाले, लेकिन इसका भाग्य बदलने में असफल रही।

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि करीब 10,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज व 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी का वहन सरकार करेगी, जिससे संभावित खरीदार पर बोझ कम किया जा सके।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'अतिरिक्त कर्ज व कुछ देनदारियों जैसे तेल कंपनियों का बकाया, एयरपोर्ट ऑपरेटर का बिल चुकाने, लंबित वेदन और स्थायी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ के भुगतान के लिए सरकार ने अलग से धन रखने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके पीछे वित्तीय बोझ कम करने का विचार है, जो कंपनी की संपत्ति के बराबर है। बाजार की स्थिति को समझने के मामले में हम व्यावहारिक हैं और हम कर्ज को लेकर खरीदार पर दबाव नहीं बना सकते।'

वित्त वर्ष 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी की संपत्ति 28,000 करोड़ रुपये है। एयर इंडिया पर 22,000 करोड़ रुपये की देनदारी है और प्राथमिक रूप से इसमें वेंडरों जैसे एयरपोर्ट और तेल कंपनियों के बकाये के अलावा कार्यशील पूंजी के लिए कम अवधि का कर्ज शामिल है।

सरकार ने पहले ही 29,500 करोड़ रुपये कर्ज विशेष उद्देश्य इकाई एयर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को स्थानांतरित कर दिया है।

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, विस्तारा, एयरएशिया इंडिया (टाटा संस की), बड़ी वैश्विक एयरलाइंस जैसे इंटरनैशनल एयरलाइंस ग्रुप और सॉवरिन व प्राइवेट ग्लोबल फंड जैसे टेमासेक, केकेआर और वारबर्ग पिंकस ने ईवाई द्वारा एयर इंडिया के लिए आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। ईवाई इस पूरी बिक्री प्रक्रिया के लिए सलाहकार है।

एयर इंडिया में सरकार का निवेश

वित्त वर्ष	राशि
2011-12	1,200
2012-13	6,000
2013-14	6,000
2014-15	5,780
2015-16	2,500
2016-17	2,465
2017-18	1,800
2018-19	3,975
कुल	29,720

स्रोतः भारत सरकार

भारत की कृषि वृद्धि दर बनी रह सकती है सुस्त

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए जीवीए

वित्त वर्ष	स्थिर मूल्य (11-12))	मौजूदा मूल्य	महंगाई दर
2014-15	-0.20	8.68	8.88
2015-16	0.60	6.29	5.64
2016-17	6.30	11.60	5.31
2017-18	3.40	4.50	1.10
2018-19	2.90	4.00	1.10
2019-20*	2.80	9.80	7.00

*नैशनल अकाउंट्स के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक
स्रोतः सीएसओ

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 7 जनवरी

भारत का कृषि और संबंधित गतिविधियों में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिर मूल्य पर 2.80 के स्तर बने रहने की संभावना है। लेकिन मौजूदा मूल्य पर जीवीए 4 साल के उच्च स्तर 9.80 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। इससे खाद्य महंगाई के संकेत मिलते हैं, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी 7 प्रतिशत बढ़ सकती है, जो 20-14-15 के बाद का बेहतर आंकड़ा है।

बहरहाल कुछ विशेषज्ञों की इससे अलग राय है। उनका कहना है कि स्थिर मूल्य व मौजूदा मूल्य पर जीवीए में अंतर किसानों की आमदनी की सही जानकारी देता है, लेकिन 2019-20 में मामला अलग है क्योंकि कुल मिलाकर हाल के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं सुधरा है।

2018-19 में स्थिर मूल्य पर जीवीए 2.90 प्रतिशत था, जबकि तत्कालीन मूल्य पर 4 प्रतिशत था लेकिन महंगाई दर में 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो जीडीपी की नई शृंखला शुरू होने के बाद का निचला स्तर था।

विशेषज्ञों का कहना है कि प्रमुख संकेतक यह है कि रबी फसल का उत्पादन कैसा रहता है। अगर उत्पादन उम्मीद से ज्यादा रहता है और कीमतें स्थिर बनी रहती हैं तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

केयर रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, 'सीएसओ द्वारा मंजूर किए गए तरीके के मुताबिक रबी की बुआई के रकबे को इसमें शामिल किया गया है। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि सीएसओ को उम्मीद है कि 2019 में भारत का रबी उत्पादन सामान्य रहेगा।'

3 जनवरी 2020 तक रबी की फसल की बुआई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 6.82 प्रतिशत ज्यादा थी और यह पिछले 5 साल के औसत रकबे की तुलना में 4.65 प्रतिशत अधिक थी।

रबी की सभी फसलों की बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में ज्यादा था। वहीं खरीफ के उत्पादन में 0.80 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई थी।

अगर ग्रामीण इलाकों में आमदनी बढ़ती है तो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, हालांकि इससे ग्रामीण इलाकों के एक छोटे हिस्से की आमदनी बढ़ती है।

क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डीके जोशी का कहना है, 'खाद्यान्न के दाम में बढ़ोतरी निश्चित रूप से उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इससे उन्हें अच्छी आमदनी होगी लेकिन ग्रामीण इलाकों में मजदूरी में बढ़ोतरी उनके लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि सब्जियों के दाम कम होंगे क्योंकि यह मौसमी होती हैं। लेकिन दलहन की महंगाई बढ़ सकती है।'

श्रम ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि सीपीआई-एएल में तेज बढ़ोतरी के कारण अक्टूबर 2019 में सामान्य कृषि श्रमिकों (पुरुष) की वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि 5.16 प्रतिशत के नकारात्मक क्षेत्र में चली गई।

कृषि व सड़क का घटेगा बजट

अरूप रायचौधरी और संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 7 जनवरी

वित्त वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा स्वीकार्य स्तर के भीतर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार बचत आगे टालकर और सीधे कटौती कर व्यय में भारी कटौती कर सकती है। वित्त मंत्रालय इसमें 2.2 लाख करोड़ रुपये की कमी करने पर विचार कर रहा है। वहीं सकल कर राजस्व में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी आ सकी है और अब विनिवेश लक्ष्य हासिल कर पाने को लेकर भी संदेह किया जा रहा है।

ज्यादातर उन विभागों व मंत्रालयों के बजट में कटौती की उम्मीद है, जिन्होंने पैसे खर्च नहीं किए हैं। इनमें कृषि, नागरिक उड्डयन, सड़क, जहाजरानी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना तकनीक, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र के अलावा अन्य मंत्रालय शामिल हैं। इंडिया रेटिंग के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा कि व्यय में कटौती की पहली कुल्हाड़ी पूंजीगत व्यय पर चल सकती है और उसके बाद सामाजिक क्षेत्र का स्थान आता है। उन्होंने कहा, 'चाहे व्यय में कटौती की जाए या उसे आगे बढ़ाया जाए, इसका असर आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा।'

अधिकारियों का कहना है कि भले ही 2 लाख करोड़ रुपये की कटौती की जाए, ऐसा लगता है कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य मुश्किल होगा। पहली बात यह है कि सालाना आधार पर नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि बजट में अनुमानित 12 प्रतिशत से बहुत कम रहेगी। दूसरे, जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने पहले खबर दी थी, वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में केंद्र को कड़े मानकों के बीच राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत तक ले जाने की छूट मिली हुई है, केंद्र सरकार की कवायद होगी कि राजकोषीय घाटा 2019-20 में 3.5 प्रतिशत के करीब रहे।

सभी विभागों में व्यय को तार्किक बनाने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले महीने नोटिस जारी कर कहा था कि विभाग साल भर के लिए आवंटित अपनी राशि का 25 प्रतिशत ही जनवरी मार्च तिमाही में खर्च करें। यह मानकों में कमी है, जबकि विभागों को आवंटित राशि का 33 प्रतिशत खर्च करने की अनुमति होती है।

जनवरी और फरवरी मिलाकर विभागों को निर्देश दिया गया कि बजट अनुमान का 15 प्रतिशत खर्च करें, जो पहले 18 प्रतिशत था, वहीं मार्च में 10 प्रतिशत खर्च करने की अनुमति दी गई, जबकि पहले 15 प्रतिशत खर्च करने की अनुमति दी गई थी।

अगर बजट के आकार को देखें तो 27.86 लाख करोड़ रुपये का 33 प्रतिशत 9.19 लाख करोड़ रुपये होता है, जबकि 25 प्रतिशत करीब 6.96 लाख करोड़ रुपये होता है। यह अंतर 2.23 लाख करोड़ रुपये है और इस तरह से खर्च में इतनी राशि कम खर्च करने को कहा गया है।

इन विभागों के व्यय में कटौती करने जा रही है सरकार

मंत्रालय	अप्रैल-नवंबर 2018-19*	अप्रैल-नवंबर 2019-20*
कृषि	70	49
नागरिक उड्डयन	83	39
मेइटी	73	59
खाद्य प्रसंस्करण	31	43
अल्पसंख्यक मामले	13	29
सड़क	75	63
जहाजरानी	77	53
पर्यटन	52	43

*बजट में निर्धारित राशि के प्रतिशत में
स्रोतः सीजीए डॉट एनआईसी डॉट इन

बीएस सूडोकू 3633 | परिणाम संख्या 3632

		3	1					6
		6			3	1		2
							3	8
	9			8	5			
		1	6		2	9		
			7	1			5	
3	4							
1		7	3			8		
8					1	6		

2	4	5	8	7	3	9	6	1
6	3	9	1	2	4	5	7	8
7	1	8	9	5	6	4	3	2
5	7	3	2	4	8	1	9	6
9	2	6	3	1	5	7	8	4
4	8	1	7	6	9	3	2	5
1	6	7	5	3	2	8	4	9
3	9	2	4	8	1	6	5	7
8	5	4	6	9	7	2	1	3

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2200/2210, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2205/2210, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1434, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1515, फ्लैक 1455, डीएमओ 1035, टरपीन लैस बोल्ड 1535

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1180/1300, खुरपा 1050/1100,चाकू 1050/1200, रसकट 930/950, शक्कर 1200/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3370, सिहोरा 3300, बुंदकी 3310, बुढ़ाना 3390,

हापुड़
गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1050/1080, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4600, खलः सरसों 2300/2400, बिनौला 2450/2600, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2250/2260, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3880/3900, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4690/4700,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2100/2125, ग्वार 3800/3850, जौ 2180/2185,

जोधपुर
गेहूं 2100/2150, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7300/7400, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4350/4450, काबली चना 5100/6000, मूंग 6400/6500,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)127, राइसब्रान (अखाद्य) 124, खल सरसों 2100, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1300,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 5900/6000, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3800/3850, शरबती स्टीम 4000/4050,चावल 1509 सेला 4700/4800, धानः शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4070/4100, हरियाणा 4050/4075, राजस्थान 4000/4075, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2275/2285, सरसों 4600/4700 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4000/4050, कपास देशी 5050/5150, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5400, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2750,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2280/2290, चावल परमल कच्चा 2450/2475, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2300/2310, बिहार 2475/2500, दाल उड़द छिलका 9200/10400, चना देशी 5150/5250, दाल चना 5400/5600, काबली चना 5300/6200, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 7900/8400,

करनाल
गेहूं दड़ा 2220/2230, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 3000/3050, पूसा 1509 धान 2800/2825, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5100/5200, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 3800/3850, जौ 1775/1780, सरसों 4250/4300, मूंग 6500/6700, गेहूं 2170/2180,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1080/1090, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 400/500, रिफाइंड (टीन) 1600/1620,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 4250/4300, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9300/9350, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3750/3800, बाजरा 1900/1950 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 277

बजट से ही आस

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पांच फीसदी रहने का जो पहला अग्रिम अनुमान लगाया है वह भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया रुख के अनुरूप ही है और अचरज में नहीं डालता है। लेकिन यह गत जुलाई में पेश आर्थिक समीक्षा में अनुमानित सात फीसदी की वृद्धि से खासा कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस वित्त वर्ष में विनिर्माण गतिविधियां दो फीसदी दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि वर्ष 2018-19 में यह 6.9 फीसदी रही थीं। इसी तरह रोजगार के लिहाज से अहम निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2 फीसदी रहने का अनुमान है जो गत वित्त वर्ष में 8.7 फीसदी रही थी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण के आंकड़े खास तौर पर चिंताजनक हैं। गत वित्त वर्ष में दस फीसदी पर रहा सकल स्थायी पूंजी निर्माण इस साल महज एक फीसदी की दर से ही बढ़ता दिख रहा है। हालांकि पिछले साल की तुलना में चालू वित्त वर्ष में सरकारी गतिविधियों में अधिक तेजी है लेकिन मौजूदा राजकोषीय स्थिति में यह भी दबाव में आ सकता है।

नॉमिनल संदर्भ में अर्थव्यवस्था के महज 7.5 फीसदी दर से ही बढ़ने की संभावना है जबकि जुलाई में बजट पेश करते समय 12 फीसदी का अनुमान लगाया गया था। अपेक्षित स्तर से सुस्त वृद्धि हालात को अपने-आप जटिल बनाएगी। मसलन, अगर समग्र रूप में सकल राजकोषीय घाटा लक्षित स्तर तक ही सीमित रहता है तो अर्थव्यवस्था के आकार में अनुमान से कम वृद्धि जीडीपी प्रतिशत में घाटा बढ़ा देगी। इसके अलावा सरकार को अपने राजस्व में 2 लाख करोड़ रुपये की संभावित गिरावट से भी निपटना होगा। सरकार के विनिवेश लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने की आशंका समस्या को और बढ़ाने का ही काम करेगी। नतीजतन, सरकार को अपने व्यय में करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये की कटौती करनी पड़ सकती है। राजस्व परिदृश्य के मद्देनजर व्यय को कुछ हद तक तर्कसंगत बनाना अपरिहार्य हो जाएगा लेकिन सरकार को आर्थिक गतिविधियों पर इसके प्रभाव को लेकर भी सजग रहने की जरूरत होगी। आंकड़े बताते हैं कि सरकारी व्यय का साथ नहीं मिलने पर वृद्धि और भी कमजोर होती। सुस्त नॉमिनल वृद्धि भारतीय कारोबारों को भी प्रभावित करेगी और कर्ज चुकाने में उन्हें अधिक मुश्किलें होने लगेंगी। यह बैंकिंग प्रणाली को दबाव में ला सकता है जिससे ऋण प्रवाह में भी कमी आएगी।

आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की संभावनाएं पश्चिम एशिया में पैदा हुए नए तनाव से धूमिल हुई हैं। कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा पड़ने और तेल के भाव बढ़ने की आशंका वैश्विक एवं घरेलू वृद्धि दोनों पर असर डालेगी। तेल कीमतों में वृद्धि और रुपये के भाव में कमी शीर्ष मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है जिससे निकट अवधि में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो जाएगी। रुपये का व्यवस्थित मूल्यह्रास जहां भारतीय निर्यातकों को मदद पहुंचाएगा वहीं वैश्विक जोखिम से बचने की कोशिश मुद्रा बाजार में अस्थिरता बढ़ा सकती है।

बहरहाल, मौजूदा स्थिति के लिहाज से वित्तीय बाजारों में जोखिम को बड़े केंद्रीय बैंकों के समझौतावादी रुख से एक हद तक संतुलित कर लिया जाएगा। वृद्धि को लेकर वैश्विक जोखिम होने के बावजूद इस समय भारत की चुनौतियां काफी हद तक घरेलू हैं। लिहाजा अर्थव्यवस्था की हालत पर नए सिरे से गौर करना होगा और सभी हितधारकों को यह देखने के लिए अब केंद्रीय बजट की तरफ नजरें टिकानी होंगी कि सरकार वृद्धि तेज करने के लिए क्या योजना बना रही है? वास्तविक आर्थिक एवं राजकोषीय स्थिति को स्वीकार करना इस लक्ष्य की तरफ उठाया जाने वाला पहला कदम होगा।

विनय सिन्हा

भारत में वृद्धि की कहानी की अधखुली परत

जीडीपी वृद्धि आंकड़ों को लेकर छिड़ी बहस के बीच हमें फिर से तीव्र वृद्धि स्तर पर पहुंचने के लिए बड़े संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इस बारे में बता रहे हैं आलोक शील

केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) की तरफ से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बारे में जारी आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2014-15 में शुरू हुआ आर्थिक विस्तार 2016-17 में 8.2 फीसदी के चरम पर पहुंच गया। उसके बाद 2017-18 में जीडीपी वृद्धि 7.2 फीसदी पर आ गई और फिर 2018-19 में यह 6.8 फीसदी हो गई। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में तो यह 4.8 फीसदी के स्तर पर लुढ़क चुकी है।

तिमाही आंकड़े बताते हैं कि 2017-18 की चौथी तिमाही में 8.1 फीसदी के शिखर के बाद आर्थिक वृद्धि लगातार छह तिमाहियों में गिरावट पर रही है और 2019-20 की दूसरी तिमाही में तो यह 4.5 फीसदी के स्तर पर आ गई। सबसे ज्यादा गिरावट 2018-19 की दूसरी तिमाही में देखी गई जब वृद्धि एक तिमाही पहले की तुलना में पूरे एक फीसदी गिरकर सात फीसदी रह गई। उसकी अगली तिमाही में यह 6.6 फीसदी और फिर 5.8 फीसदी पर आ गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी गिरकर पांच फीसदी और फिर 4.5 फीसदी रह गई।

अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर मतभेद है कि वृद्धि में आई गिरावट चक्रीय है या संरचनात्मक। इसके अलावा जीडीपी आकलन के लिए 2011-12 को नया आधार मानने से जुड़ा विवाद भी अभी तक सुलझा नहीं है। ये सारे आंकड़े इस नए आधार वर्ष के ही आधार पर जारी किए गए हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और तत्कालीन आरबीआई गवर्नर दोनों ने ही 2011-12 सीरीज को वर्ष 2015 में लागू करते समय आशंकाएं जताई थीं। इसकी वजह यह है कि नए आंकड़े उच्च आवृत्ति वाले आंकड़े से मेल नहीं खाते हैं।

नई जीडीपी सीरीज के आधार पर पिछले आंकड़े सामने आने पर यह ताज्जुब और भी बढ़ गया। वर्ष 2003-04 से लेकर 2007-08 की अवधि के लिए जीडीपी के 2004-05 सीरीज आधारित अनुमानों को संशोधित करते हुए 8.8 फीसदी से घटाकर 7.8 फीसदी कर दिया गया। इसका मतलब है कि वैश्विक तेजी के इस दौर में भारत की औसत वृद्धि दर 2014-15 और 2018-19 की अवधि में रही 7.5 फीसदी वृद्धि से महज 30 आधार अंक ही अधिक थी जबकि पुराने अनुमानों के हिसाब से 130 आधार अंकों का फर्क था। खास बात यह है कि सरकार ने ये संशोधन एक दशक बाद किए थे।

इन संदेहों को बल देने वाली बात यह थी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा रियल सेक्टर सांख्यिकी पर गठित समिति के तकनीकी विशेषज्ञों ने यह गणना की थी। इन गणनाओं में दिखा कि तीव्र वृद्धि के काल में जीडीपी वृद्धि असल में कहीं अधिक थी।

विरोधी नेता इन आंकड़ों को लेकर सार्वजनिक रूप से भिड़ गए। इसकी वजह यह थी कि भले ही संप्रग-2 के समय वृद्धि कायम नहीं रही लेकिन संप्रग-1 यानी 2004-09 के दौरान वृद्धि 2014-19 के दौरान सत्तारूढ़ राजग सरकार से अधिक तेज थी। इसकी एक वजह यह है कि संप्रग-1 के समय वैश्विक तेजी का माहौल था।

जीडीपी आंकड़ों को लेकर जारी बहस में अरविंद सुब्रमण्यन भी कूद पड़े हैं। उन्होंने गत जून एवं जुलाई में दो शोध-पत्रों के प्रकाशन के बाद इन पर अपनी राय रखी है।

पहला, उन्होंने भारत के वृद्धि रुझानों की तुलना समान आधार वाले प्रमुख विकासशील देशों से की। दूसरा, उन्होंने प्रमुख जीडीपी आंकड़ों और उच्च आवृत्ति संकेतकों के बीच विसंगतियों पर भी गौर किया। इस आधार पर उन्होंने अनुमान जताया कि 2011-12 से आगे की अवधि के लिए भारत की वृद्धि सीएसओ अनुमान से करीब 2.5 फीसदी कम थी। उनके दूसरे पत्र में ये दलीलें दोहराए जाने के बावजूद अधिमूल्यांकन से बचने की कोशिश की गई थी। जीडीपी वृद्धि के आंकड़े मोटे तौर पर दूसरे आर्थिक आंकड़ों से मेल खाने चाहिए ताकि वृहद-आर्थिक तर्क पर उन्हें परखा जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो जीडीपी आंकड़ों पर नए सिरे से गौर करने की जरूरत है।

इस तरह के कई डेटा समूहों के बारे में सोचा जा सकता है जिनका जीडीपी वृद्धि दर के मजबूत सकारात्मक सह-संबंध है। ऐसे मौके हो सकते हैं जब कुछ विशेष कारणों से एक खास संकेतक अल्प समय के लिए तालमेल में न रहा हो। सामूहिक तौर पर देखें तो यह कल्पना कर पाना मुश्किल है कि शीर्ष संकेतकों को जीडीपी से सकारात्मक सह-संबंध न हो। ऐसे सारे संकेतक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राष्ट्रीय आय की गणना का हिस्सा बनते हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक, ऑटो उत्पादन, बिजली उत्पादन, रेल-सड़क-वायु मालवहन, निर्यात, केंद्रीय कर राजस्व, कॉर्पोरेट मुनाफा, रोजगार, बैंक क्रेडिट, सूचना प्रौद्योगिकी बाजार का आकार, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सेंसेक्स जैसे संकेतकों पर गौर किया जाता है। जहां कहीं भी मौद्रिक आंकड़ों का इस्तेमाल होता है वहां वे थोकमूल्य एवं उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के औसत से अपस्फीतिकारी होते हैं। इसका कारण यह है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि से तुलना की जाती है। डॉलर के वर्चस्व वाली सीरीज को अंकित मूल्य पर लिया जाता है।

कुल मिलाकर ये डेटा समूह 2003-04 और 2007-08 के बीच जबरदस्त वृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। उसके बाद 2008-09 और 2009-10 में वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट के बीच इसमें भारी गिरावट आई। हालांकि 2010-11 में बहुत तेजी से हालात सुधरे और वृद्धि ने रफ्तार पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद वृद्धि गिरी और पिछली अवधि से काफी नीचे आ गई।

आंकड़े बताते हैं कि नई सरकार के काम संभालने के बाद 2014-15 और 2017-18 के बीच वृद्धि में मामूली सुधार ही हुए। हालांकि नोटबंदी एवं दोषपूर्ण कर सुधार (जीएसटी) की वजह से यह फिर से नीचे चली गई। आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 और 2018-19 के बीच कुल वृद्धि 2003-04 और 2007-08 के दौर की वृद्धि से साफ तौर पर कम थी।

एक समग्र मूल्यांकन के अभाव में जीडीपी वृद्धि के प्रामाणिक वैकल्पिक आंकड़े पेश कर पाना मुश्किल है। वैसे यह आंकड़ा सुब्रमण्यन के उस आकलन से काफी हद तक मेल खाता नजर आता है कि 2011-12 के परवर्ती काल में जीडीपी वृद्धि को 2-2.5 फीसदी तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। इसका मतलब है कि 2014-15 और 2018-19 के बीच औसत वृद्धि दर पांच फीसदी के करीब हो सकती है जबकि सीएसओ ने 2011-12 सीरीज के आधार पर इसके 7.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। एक मतलब यह भी है कि फिलहाल जीडीपी महज 2-2.5 फीसदी की दर से ही बढ़ रही है।

निष्कर्षत: अगर विवादास्पद जीडीपी आंकड़ों को परे रखकर अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो यह पता चल जाएगा कि 2011-12 के बाद से ही वृद्धि के मोर्चे पर सुधार कमजोर ही रहा है। वर्ष 2003-08 के समय के उच्च स्तर से वृद्धि संभावना में होने वाली गिरावट हिस्टैरिसिस प्रक्रिया के आधार पर संरचनात्मक नजर आएगी। दूसरी तरफ, पिछली कुछ तिमाहियों में आई तीव्र गिरावट निम्न आधार वाली जीडीपी पर संभवत: चक्रीय हो सकती है।

जहां वृहद-आर्थिक नीतियां वृद्धि को दोबारा पांच फीसदी पर लौटा सकती हैं वहीं वृद्धि संभावना को 2003-08 के स्तर के आसपास भी लाने के लिए बड़े संरचनात्मक सुधारों की जरूरत होगी। पुराने मुद्दों के अलावा बैंकिंग प्रणाली की खामियां दूर करना, सरकार एवं आर्थिक गतिविधियों के बीच खोए भरोसे को बहाल करना और एक सुविचारित, अनुमानित एवं भविष्योन्मुख नीति का रोडमैप बनाना होगा।

(लेखक इक्रियर संस्थान में आरबीआई पीठ के प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

लोकलुभावनवाद के दौर में देश के 'फंसे हुए' कामगार

नीति नियम

मिहिर शर्मा

वित्तीय प्रबंधन 'फंसी हुई परिसंपत्तियों' की समस्या को लेकर सजग हुआ है। इन संपत्तियों का आशय ताप बिजलीघरों जैसे प्रतिष्ठानों से है जो आर्थिक या राजनीतिक हालात बदलने से समय से पहले ही अनुत्पादक होते जा रहे हैं। मसलन, कोयला संयंत्रों का सवाल है तो जलवायु परिवर्तन संबंधी कानून मजबूत बनाए गए हैं, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं और सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक तकनीकें अनुमान से अधिक प्रतिस्पर्द्धी हो चुकी हैं। बहीखातों की मजबूती एवं बैंकों का ऋण जोखिम परखते समय इन समस्याओं को भी ध्यान में रखना होगा। यही वजह है कि कोयला खनन के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोलने पर सरकार का जोर देना खतरनाक हो सकता है जब राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हें फंड कर रहे हों। इससे आगे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बन सकती हैं।

फिर भी विकास की योजना बनाते समय फंसी परिसंपत्तियों की समस्या का एक सादृश्य फंसे हुए कामगारों का है। दुनिया भर में ऐसे फंसे कामगार लोकलुभावनवाद के उभार में सबसे खास कारक साबित हुए हैं। अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में पिछले तीन-चार वर्षों में हुए व्यापक बदलावों पर गौर कीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप को अप्रत्याशित समर्थन औद्योगिक एवं खनन के लिए मशहूर रहे इलाकों में मिला। ब्रिटेन के उत्तर में मौजूद औद्योगिक एवं खनन इलाके में परंपरागत तौर पर श्रमिकों की बहुलता रही है और वे टोरी विचारधारा को नापसंद करते रहे हैं लेकिन हाल ही में संपन्न संसदीय चुनावों में उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को खुलकर समर्थन देकर बोरिस जॉनसन को जिताने में मदद की। इस बीच फ्रांस के 'पीली जैकेट' प्रदर्शन इस परिघटना की शायद सबसे मुखर अभिव्यक्ति करते हैं। सत्ता-विरोधी प्रदर्शनों ने पिछले साल अक्सर फ्रांस के शहरों एवं कस्बों को थमने के लिए मजबूर कर दिया था। राजनीतिक विचारक मैंकर ओल्सन की अवधारणा यह है कि सुधारों की राह में रोड़े अटकाने वाले गठजोड़ बनाना समर्थक गठजोड़ तैयार करने की तुलना में अधिक आसान है। सुधारों के लाभ अक्सर अनिश्चित एवं अव्यवस्थित होते हैं। किसी को भी पक्का पता नहीं होता है कि अमुक सुधार से उन्हें निजी तौर पर क्या कुछ मिलेगा? वहीं सुधारों के प्रति आशंकित लोग नुकसान को लेकर आश्वस्त होते हैं। ऐसे में आक्रोशित 'पराजितों' को एकजुट करना कहीं अधिक आसान है। दुनिया के कई हिस्सों में इस समय दिख रही समस्या एकदम साफ है। इसका ठीकरा अक्सर 'भूमंडलीकरण' या व्यापार पर मढ़ा जाता है। मसलन, अर्थशास्त्री डेविड ऑटर का 'चीन सदमा' सिद्धांत कहता है कि चीन से व्यापार के चलते अमेरिका के रस्ट बेल्ट इलाके में गंभीर बेरोजगारी देखी गई है। वैसे इस अवधारणा पर पूरी सहमति नहीं बनी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पेश कर रहे एंड्रयू यांग जैसे लोगों का मानना है कि ऑटोमेशन जैसे तकनीकी बदलाव भी 'फंसे हुए कर्मचारी' बना सकते हैं।

ऐसे बदलावों के चलते लाक्षणिक रूप से फंसे कामगारों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक असर उस समय कई गुना बढ़ जाते हैं जब वे वास्तव में भी फंसे हुए होते हैं। यानी, ये कामगार किसी वजह से अपने स्थान से दूर नहीं जा पाते हैं तो वे तकनीकी या नियामकीय बदलावों का अधिक लाभ उठाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। किसी भी बदलाव का वेतन एवं श्रमिक कल्याण पर पूरे असर के लिए श्रम गतिशीलता अहम है। पिछली सदी में दक्षिण-मध्य अमेरिका के डस्ट बाउल से हटकर रोजगार पूर्वी तट की ओर चला गया था जिसके लिए मौसमी बदलावों से कृषि के अलाभकारी हो जाने के अलावा कैलिफोर्निया में आजीविका की उम्मीदें भी थीं। वहां जाने वाले अधिकतर लोग सफेदपोश कार्यों से जुड़े हुए थे। लेकिन सामाजिक सुरक्षा ढांचा नहीं होने से यह एक मानव त्रासदी में तब्दील हो गया। अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक संतुलन लाने के लिए यह आवक अहम थी। आज की अर्थव्यवस्था में ऐसा संतुलन आसानी से नहीं पाया जा सकता है क्योंकि भौगोलिक आवाजाही उतनी आसान नहीं रह गई है। सुस्ती के दौर में दूसरी जगह जाने पर पूंजी का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा सामाजिक कारण भी हैं, एकजुट हो चुके समुदाय खुद को अलग होते नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन यह एकजुटता राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से 'बाहरी' लोगों के खिलाफ भी तब्दील हो सकती है। भारत को फंसी हुई जनसंख्या के सृजन को लेकर सजग रहना होगा। हाल के वर्षों में बड़े औद्योगिक केंद्र नहीं बन पाने से यह मान लेना आसान है कि ये समस्याएं भारत के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि भारत समेत तमाम देशों में फंसे कामगारों को यह बात एकजुट करती है कि व्यापक आर्थिक, तकनीकी या जलवायु बदलावों के नाते उनकी अपेक्षाएं हकीकत से मेल नहीं खाती हैं। भारत में हम परंपरागत तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में कामगारों को लेकर चिंतित होते थे। इसी वजह से निजीकरण सियासी तौर पर विवादित रहा है। लेकिन हमें आर्थिक रूप से कम गतिशील इलाकों में फंसे और केवल खुदरा क्षेत्र या सूक्ष्म विनिर्माण गतिविधियों में ही दक्ष दस या सौ कर्मचारियों के लिए भी फिक्र करनी होगी। तकनीक बदलने से इन क्षेत्रों में श्रमिकों की जरूरत कम हो जाएगी। उन्हें नए कौशल के हिसाब से प्रशिक्षित करने और देश भर में भ्रमण को अधिक दिलचस्प बनाने की जरूरत है।

कामगारों का नए इलाकों में स्वागत किया जाए जहां उन्हें आवास एवं पसंदीदा खानपान भरपूर मिले। और उन जगहों को भी आश्वस्त करना होगा कि उनकी सांस्कृतिक पहचान या राजनीतिक स्वायत्तता गंवा रहे हैं। भारत में फंसे कामगारों की समस्या बाकी दुनिया जैसी ही है लेकिन उसमें बुनियादी प्रशिक्षण और संघवाद के अलग मॉडल की भी जरूरत है। इन बिंदुओं पर फौरन ध्यान नहीं दिया गया तो बाकी दुनिया में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता भारत पर सौ गुना भारी पड़ेगी।

कानाफूसी

कूटनीतिज्ञ अखिलेश

पिछले दिनों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) ने पार्टी प्रमुख तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी (बसपा), दोनों दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। हालांकि इस प्रयोग से वांछित परिणाम हासिल नहीं हुए और सभी दल गठबंधन से अलग हो गए। अब उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा तथा कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर दबाव बना रही हैं जिससे इसे 2022 चुनाव से पहले एक अहम मुद्दा बनाया जा सके। फिलहाल अखिलेश यादव सावधानीपूर्वक अपने कदम बढ़ा रहे हैं ताकि विपक्षी साथियों को नाराज न किया जाए। हालांकि बसपा और कांग्रेस दूसरे विपक्षी दलों पर भी बयानबाजी कर रही हैं लेकिन यादव अपने विचार पर अडिग हैं तथा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर ही लगातार हमला बोल रहे हैं।

पीआईबी कार्ड की जगह आधार

नया वर्ष मीडियाकर्मियों के लिए कुछ अनोखी मांग के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत तथा पुलिस की मंजूरी के बाद जारी होने वाला पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) कार्ड की विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। नॉर्थ ब्लॉक से लेकर साउथ ब्लॉक तथा राष्ट्रपति भवन जैसे पांच प्रमुख मंत्रालयों तक पहुंच बनाने के लिए बने संपर्क कार्यालयों ने काफी समय पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि पीआईबी कार्ड इस संबंध में उपयोग के लिए नहीं हैं और परिसर में अधिकारियों से मिलने के लिए आंतरिक प्रणाली का उपयोग किया जाए। हालांकि इसमें अब एक नया बदलाव देखने को मिला है। कुछ जाने माने मंत्रालय आगंतुक पास लेने के लिए स्वागत कक्ष पहुंचने से पहले ही बाहरी द्वार पर भी पीआईबी कार्ड दिखाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही एक मंत्रालय में तैनात सुरक्षा गार्डों को स्वागत कक्ष पर जाने के लिए एक पत्रकार से प्रामाणिक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। एक कर्मी ने गंभीर स्वर में कहा, 'हमें पीआईबी कार्ड की जगह कुछ और दें... अपना आधार कार्ड दिखाएं।' हालांकि वे यह नहीं बता पाए कि आधार को पसंदीदा दस्तावेज में शामिल क्यों किया गया।

आपका पक्ष

स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों

सरकार हरेक नागरिक को सस्ती और उचित सेवाएं उपलब्ध कराने का दावा करती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी खबरें आ जाती हैं जो देश को स्वस्थ रखने और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के दावों की पोल खोल देती हैं। राजस्थान के अस्पतालों में सैकड़ों बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। जब तक देश के गरीबों को उचित दामों पर इलाज नहीं मिलता, तब तक देश के विकास के दावे खोखले साबित होंगे। सरकारी नीतियों में प्राथमिकता रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सुविधाओं को दी जानी चाहिए। भारत जहां योग और जड़ी बूटियों से हर छोटी बीमारी का इलाज करने में दुनियाभर में नंबर एक माना जाता है, वहां महंगे इलाज कारण लोगों की मौत हो जाना या फिर इलाज के लिए गरीब और मध्यम परिवार को अपनी जमीन-जायदाद गिरवी रखना दुखदायी और अफसोसजनक है। किसी देश की संपन्नता जीडीपी के आंकड़े या शेयर अंकों से पता नहीं चलती है बल्कि नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दो वक्त की रोटी व अन्य सुविधाओं की स्थिति से इसका पता चलता है। कुछ समय पहले नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ निजी संस्थानों से करार किया जाए। एक स्वस्थ नागरिक ही देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। आज सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा दिखाई पड़ती है। भारत में आबादी और बीमारियां बढ़ती गईं लेकिन डॉक्टरों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी। डॉक्टरों की कमी का मुख्य कारण मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम होना और इनमें प्रवेश के लिए लाखों रुपये का डोनेशन जिम्मेदार है। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी बढ़ावा और इसमें युवाओं की रुचि बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत आयुर्वेद प्रधान देश है। मोदी सरकार को देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने, सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं देने और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के प्रयास किए जाने चाहिए

समान नागरिक संहिता जरूरी

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी मूल्य समानता है। लेकिन बहुलतावादी संस्कृति, पुरातन परंपराएं और धर्मनिरपेक्ष राज्य समानता को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे धार्मिक समुदाय शिक्षित होते जा रहे हैं वैसे ही निजी कानून और मान्यताएं निष्प्रभावी होती जा रही है। पिछड़ा तबका शिक्षित होकर मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। कुछ मामलों में न्यायालयों ने भी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जिससे हरेक धर्मावलंबी के लिए व्यक्तिगत रूप से संविधान सम्मत धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था के अनुरूप कदमताल मिलाने के अवसर खुलते जा रहे हैं। बहरहाल समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करते समय व्यापक राय मशविरे की जरूरत है। देश में लोक परंपराओं और मान्यताओं में समानताएं तलाशते हुए, उन्हें भी विधि सम्मत एकरूपता में ढालने की जरूरत है। अगर ऐसी तरलता बरती जाती है तो शायद निजी कानून और मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में अदालतों को जिन कानूनी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है वे दूर हो जाएं और देश समृद्ध और खुशहाल हो सके।

हरिओम हंसराज, सारण

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कॉफी निर्यात 2019 में 3.50 लाख टन रहा

भाषा
नई दिल्ली, 7 जनवरी

देश का कॉफी निर्यात 2019 में मामूली बढ़कर 3.50 लाख टन हो गया। इससे पिछले साल 3.48 लाख टन कॉफी का निर्यात किया गया था। भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक देश है। भारतीय कॉफी का निर्यात सबसे ज्यादा इटली, जर्मनी और रूस में किया गया। रोबस्टा और अरेबिका कॉफी के अलावा इंस्टेंट कॉफी का निर्यात करता है।

कॉफी बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रोबस्टा कॉफी का निर्यात 4.10 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 1,86,360 टन पर पहुंच गया। वर्ष 2018 में यह आंकड़ा 1,79,004 टन पर था। हालांकि, अरेबिका कॉफी का निर्यात 2018 में 53,049 टन से घटकर 2019 में 47,341.82 टन पर आ गया। इस दौरान निर्यात में 10.75 प्रतिशत की गिरावट रही।

इंस्टेंट कॉफी का निर्यात भी गिरकर 27,339 टन पर आ गया जबकि 2018 में 29,146 टन कॉफी का निर्यात किया गया था। भारत के लिए 2019 में इटली शीर्ष निर्यात बाजार रहा। भारत ने इटली को 72,267 टन, जर्मनी को 37,175 टन और रूस को 28,573 टन कॉफी का निर्यात किया है।

रिफाइनरों को मलेशिया से पाम तेल खरीद रोकने की ताकीद

नागरिकता कानून पर मलेशिया की टिप्पणी से भारत में नाराजगी

रॉयटर्स
मुंबई /नई दिल्ली, 7 जनवरी

कश्मीर में भारत की कार्रवाई और नए नागरिकता कानून की मलेशिया द्वारा आलोचना किए जाने के बाद भारत ने अनौपचारिक तौर पर पाम तेल रिफाइनरों और व्यापारियों को मलेशिया से पाम तेल खरीद से बचने के लिए कहा है। सरकार और उद्योग के सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। भारत पाम तेल का दुनिया का बड़ा खरीदार है और अगर भारतीय रिफाइनरों ने मलेशिया से पाम तेल की खरीद कम कर दी तो मलेशिया में पाम तेल का स्टॉक बढ़ सकता है जिससे दामों पर दबाव बनने के आसार हैं। पाम तेल की कीमतों के लिए मलेशिया के दाम वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क रहते हैं। भारत के वनस्पति तेल उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि सरकार ने सोमवार को नई दिल्ली में वनस्पति तेल उद्योग के दो दर्जन अधिकारियों की बैठक के दौरान रिफाइनरों को मलेशिया का बहिष्कार करने के लिए कहा है। अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में हमें मौखिक रूप से मलेशिया के पाम तेल की खरीद से बचने के लिए कहा गया है।

भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि हम मलेशिया से किस तरह आयात में कटौती कर सकते हैं, इस संबंध में हमने सरकार और उद्योग के साथ कई दौर की मुलाकात की थी। अधिकारी ने कहा कि भारत को कार्रवाई करने और विभिन्न विकल्प तलाशने के लिए ठोस योजना तैयार करनी है।

मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कश्मीर में भारत की कार्रवाई और नए नागरिकता कानून पर जो टिप्पणी की है, उससे भारत में नाराजगी है। अक्टूबर में भारतीय कारोबारियों ने मलेशिया के साथ कुछ समय के लिए नए अनुबंध बंद कर दिए थे और यह डर पैदा हो गया था कि भारत मलेशिया के पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ा देगा। महातिर ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा था कि भारत ने हमला करके कश्मीर पर कब्जा किया है जो मुस्लिम बहुल वाला विवादित क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान द्वारा भी दावा किया जाता है।

पिछले महीने महातिर ने भारत के नए नागरिकता कानून के संबंध में कहा था कि इस कानून की वजह से लोग मर रह हैं। जब तकरीबन 70 सालों से लोग नागरिक के तौर पर बिना किसी दिक्कत के एक साथ रह रहे हैं, तो ऐसा करने की क्या जरूरत है।

उद्योग के अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत ने स्पष्ट किया है कि वह मलेशिया को उसकी टिप्पणी के लिए दंड देना चाहता है और व्यापारियों को इसमें सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण सरकार मलेशिया से आयात रोकने के लिए रास्ते तलाशने के प्रयास कर रही है। फिलहाल सरकार ने उद्योग को सहयोग करने के लिए कहा है।

इंडोनेशिया से बढ़ सकता है भारत का पाम तेल आयात

दिसंबर में सोया खली निर्यात 79 फीसदी घटा

भाषा
नई दिल्ली, 7 जनवरी

सोयाबीन खली के निर्यात में भारी गिरावट आने की वजह से देश से दिसंबर माह में सोया खली का निर्यात 79.20 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 67,562 टन रह गया। तेल उद्योगों के प्रमुख संगठन एसईए ने यह जानकारी दी। भारतीय सोयाबीन सोया खली के दाम ऊंचे होने की वजह से मांग कमजोर रही। देश से दिसंबर 2018 के दौरान 3,24,927 टन तिलहन का निर्यात किया गया। खली और इससे तैयार अन्य उत्पादों का उपयोग मुर्गी और अन्य क्षेत्रों के पशु आहार में किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान खली का कुल निर्यात 25 प्रतिशत घटकर 18.02 लाख टन रहा जबकि एक साल पहले यह निर्यात 24.11 लाख टन रहा था। एसईए ने एक बयान में कहा, 'इसका मुख्य कारण अन्य देशों की तुलना में विशेषकर सोयाबीन खली की कीमत का कम नहीं होना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिक होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू सोयाबीन खली अन्य देशों के मुकाबले महंगी पड़ती है।' इसने कहा कि सोयाबीन खली का निर्यात दिसंबर 2019 के दौरान काफी घटकर 5,876 टन रह गया, जो साल भर पहले इसी माह में 1,70,588 टन थी। इसी तरह, रैपसीड एक्सट्रैक्ट का निर्यात पहले के 87,106 टन से घटकर 24,609 टन रह गया, जबकि चावल भूसी खली का निर्यात पहले के 49,060 टन से घटकर 3,550 टन रह गया। हालांकि, दिसंबर 2019 में अरंडी खली का निर्यात लगभग 60 प्रतिशत बढ़कर 4,69,248 टन हो गया, जो दिसंबर 2019 में 2,92,511 टन रहा था। भारतीय तेल मिलों का मुख्य निर्यात गंतव्य दक्षिण पूर्व एशियाई देश, पश्चिम एशियाई देश के साथ ही जर्मनी अन्य यूरोपीय देश और अमेरिका हैं।

अबतक 12,000 टन प्याज का आयात

राज्यों को 49-58 रुपये किलो के भाव पर

भाषा
नई दिल्ली, 7 जनवरी

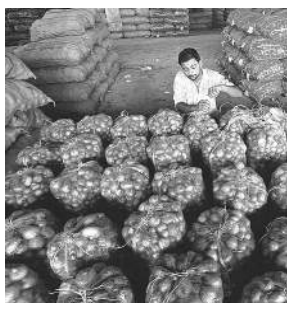

सरकार ने प्याज की आपूर्ति बढ़ा कर इसकी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए अब तक 12,000 टन प्याज का आयात किया है। सरकार राज्यों को इसे 49 से 58 रुपये किलो के भाव पर पेश कर रही है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'हमने तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों से अभी तक 12,000 टन प्याज का आयात किया है।' सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेडिंग कंपनी एमएमटीसी के माध्यम से प्याज का आयात कर रही है और निजी आयातकों को भी सुविधा दे रही है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल को पहले ही 1,000 टन आयातित प्याज दिया जा चुका है। इस महीने के अंत तक और 36,000 टन विदेशी प्याज की खेप पहुंचने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि इससे कीमतों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

पिछले दो महीनों से प्याज 100 रुपये किलो के दायरे में था पर अब आयातित प्याज और नई खरीफ की फसल की आवक से प्याज का बाजार नरम होने लगा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्याज का भाव मंगलवार को 70 रुपये किलो था। गत 19 दिसंबर को यह 118 रुपये किलो पर चल रहा था। इसी तरह मुंबई में प्याज कीमत 120 रुपये से घटकर अब 80 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। खरीफ के प्याज की फसल 25 फीसदी घटने से प्याज का बाजार चढ़ा हुआ है।

- भारत ने तुर्की और अफगानिस्तान से प्याज का आयात किया
- प्याज का आयात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी के माध्यम से किया गया
- दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल को पहले की जा चुकी है 1,000 टन आयातित प्याज की आपूर्ति

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 7	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,791.0	4.6	2,032.6	2.4
Copper	6,097.5	8.4	6,501.5	9.7
Nickel	13,795.0	-23.1	14,548.2	-21.1
Lead	1,900.0	-13.2	2,171.8	2.2
Tin	16,875.0	2.0	17,680.6	0.5
Zinc	2,335.0	0.3	2,561.6	-1.1
Gold ($/ounce)	1,569.3*	5.1	1,748.3	4.9
Silver ($/ounce)	18.2*	4.2	20.4	3.9
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	68.8*	17.3	70.0	20.0
Natural Gas ($/mmBtu)	2.1*	-8.3	2.1	-9.0
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	191.6	13.7	315.3	7.4
Maize	192.3*	6.7	329.7	9.4
Sugar	364.2*	7.2	486.8	-1.5
Palm oil	782.5	49.0	1,211.7	42.5
Rubber	1,623.6*	16.9	1,837.7	8.3
Coffee Robusta	1,325.0*	5.7	1,851.6	-6.1
Cotton	1,537.5	14.8	1,615.7	-0.4

* As on Jan 07, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.8& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	71.9	23420
Oil and Oilseeds	431.1	57972
Spices	2.7	12
Metal(Jan 06)		
Metal- non ferrous	5301.2	46728
Metal- precious	17835.3	412
Oil and gas(Jan 06)		
Gas	2689.8	51280
Oil	19637.7	1983

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	156.8	121204
Grains	172.7	103630
Oil and Oilseeds	1333.7	535900
Others	135.7	70945
Pulses	54.0	37840
Spices	97.1	28605

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Crude Palm Oil (Jan 31)	805.5	1.4
Gold Guinea (Jan 31)	32255.0	1.2
Aluminium Mini (Jan 31)	141.5	1.1
Copper (Jan 31)	446.3	1.0
Gold Petal (Jan 31)	4026.0	1.0
Gold Mini (Feb 05)	40448.0	1.0
Gold (Feb 05)	40472.0	0.9
Crude Oil (Jan 17)	4538.0	0.9
Zinc Mini (Jan 31)	181.5	0.7
Kapas (Apr 30)	1128.0	0.6
Nickel (Jan 31)	1023.7	0.4
Losers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3885.8	-3.9

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6446.0	2.7
GuarGum 5T-Jodhpur (Jan 20)	7356.0	0.7
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1129.5	0.5
Chana-Bikaner (Jan 20)	4484.0	0.5
Guar Seed 10 (Jan 20)	4098.0	0.5
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Jan 20)	914.6	0.2
Losers (* % Change)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6234.0	-4.3
Bajra (Jan 20)	1986.0	-1.9
CastorSeed New-Disa (Jan 20)	4200.0	-0.7
Jeera Unjha (Jan 20)	16035.0	-0.6
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4463.0	-0.4
CottonSeed Oil-Akola (Jan 20)	2095.0	-0.1

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19730.0	2.9
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	1.6
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	47559.0	1.0
Silver Ahm (Mar 05)	47546.0	0.9
Gold Ahm (Feb 05)	40472.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1289.0	-8.4
Aluminium Mum (May 29)	137.6	-5.2
Alumini-Mumbai (Jan 31)	141.5	-2.6
Lead Mum (May 29)	152.1	-2.2
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	181.5	-2.0
Lead Min Mumbai (Jan 31)	152.5	-1.9
Copper Mum (Jan 31)	446.3	-1.8

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6446.0	4.0
Paddy-Basmati-Karnal (Jan 20)	3308.0	3.4
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	820.5	0.7
Barley Jaipur (Jan 20)	2223.0	0.5
Bajra-Jaipur (Jan 20)	1986.0	0.2
Discount over spot price (In %)		
Coriander-Kota (Jan 20)	6234.0	-8.7
Soy Bean Indore (Jan 20)	4196.0	-2.9
Moong-Merta City (Jan 20)	7396.0	-1.4
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Jan 20)	7356.0	-1.2
Jeera Unjha (Jan 20)	16035.0	-1.1
Bajra-Delhi (Jan 20)	1986.0	-0.5

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	109.....(106)
Aluminium ingots /kg	146.....(145)
Brass sheet cutting /kg	333.....(330)
Brass utensil scraps/kg	313.....(312)
Copper heavy scrap /kg	434.....(431)
Copper utensil scraps/kg	403.....(402)
Copper wire bar /kg	467.....(464)
Lead ingots /kg	156.....(156)
Nickel Cathodes /kg	1045.....(1045)
Tin slabs /kg	1270.....(1275)
Zinc slabs /kg	184.....(184)
Source:Bombay Metal Exchange	
Cotton	**Mumbai**
Bengal Deshi /Qtl	10320.....(10320)
DCH - 32 /Qtl	11389.....(11332)
Jaydhar /Qtl	9926.....(9926)
Shankar- 6 /Qtl	11192.....(11135)
Source:Cotton Association of India	
Oil	**Mumbai**
Castor FSG /10kg	895.....(895)
Castor Comm /10kg	885.....(885)
Groundnut oil /10kg	1130.....(1150)
Palm oil /10kg	868.....(874)
Sunflower exp ref /10kg	925.....(930)
Sunflower oil exp /10kg	895.....(900)
Soyabean ref / 10kg	910.....(920)
Source:Bombay Commodity Exchange	

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3392-3602.....(3392-3582)
Source:Bombay Sugar Merchants Association	

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	62.78.....(63.27)
Brent Crude (UK)	68.64.....(69.02)
Brent Crude (WTI)	62.78.....(63.27)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.11.....(2.14)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	331.93.....(335.67)
Naptha spot /Rs/MT	45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com	

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40375.....(40678)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40537.....(40842)
Silver.999/ kg	47145.....(47955)
Source:India Bullion & Jewellers Association	

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18988.75	19077.45
Alumini-Mumbai (M)	1 K	143.70	145.20
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2020.00	1995.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1994.15	1981.05
Barley Jaipur (N)	1 Q	2217.85	2210.85
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3967.00	3908.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4300.00	4291.65
Castor Seed-Kadi (N)	X	4232.50	4242.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4378.10	4393.05
Chana Delhi (N)	1 Q	4575.00	4582.50
Chana-Akola (N)	X	4450.00	4450.00
Coriander-Gondal (N)	X	6567.00	6569.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6850.00	6800.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6878.80	6830.90
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2135.05	2127.50
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2080.55	2106.65
Cotton-Kadi (N)	1 B	18985.15	19122.60
CPO-Kandla (M)	10 K	799.50	801.50
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	817.40	814.40
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	807.50	805.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	920.45	916.00
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1565.40	1559.35
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3479.15	3479.10
Gold Ahm (M)	10 G	40678.00	40372.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32673.00	32427.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4081.00	4050.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7342.15	7448.20
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4008.20	4075.90
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3975.00	3992.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1129.25	1164.65
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	99.30	99.95
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16700.00	16700.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16211.10	16214.30
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	942.20	935.20
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1043.25	1052.15
Kapas-Rajkot (N)	X	1048.00	1044.85
Lead Mum (M)	1 K	154.00	155.45
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2031.90	2014.40
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2447.75	2438.65
Maize-Erode (N)	X	2073.90	2072.10
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2227.50	2200.00
Maize-Sangli (N)	X	2072.70	2081.35
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	5025.00	5000.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7550.00	7500.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4643.00	4643.00
Mustardseed Oil-Srig (N)	X	-	438.20
Nickel Mumbai (M)	1 K	1030.70	1041.70
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3221.00	3164.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3300.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	345.00	345.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35000.00	34825.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	-	920.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	843.00	808.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2050.85	2030.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	-	5122.55
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	870.00	870.40
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	922.35	917.45
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	931.30	921.15
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	948.75	942.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13200.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13200.00	13217.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	47941.00	47099.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4326.00	4323.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4343.00	4269.25
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4363.20	4343.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4307.00	4282.00
Soymeal Indore (N)	1 T	35500.00	34975.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	929.00	917.50
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	32000.00	32000.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	32510.00	32300.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	30320.00	29740.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3295.00	3345.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3447.60	3428.55
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3302.50	3320.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3533.35	3519.05
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3328.75	3350.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3151.25	3185.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6138.65	6196.60
Wheat Delhi (N)	1 Q	2366.25	2368.75
Wheat Kota (N)	1 Q	2260.00	2280.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2320.00	2325.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2190.00	2190.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2330.00	2355.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5700.00	5700.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5600.00	5612.50
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.60	185.10

* as on Jan 06, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (मंगलवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19770, 19860, 19710, 19730	4957	665	19196
Feb 28	20070, 20120, 19990, 20000	910	138	3231
Mar 31	20330, 20330, 20330, 20330	43	1	128
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Jan 20	2107, 2120, 2082, 2095	20710	1323	38830
Feb 20	2131, 2145, 2106, 2121	37340	2536	68020
Mar 20	2158, 2165, 2130, 2144	1760	169	7500
Apr 20	2184, 2185, 2160, 2170	560	50	2360
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1125, 1132, 1125, 1128	512	74	848
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1124.5, 1134, 1124, 1129.5	1277	727	4494
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	2030, 2030, 1980, 1986	170	6	260
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4092, 4132, 4074, 4098	11690	1426	35070
Feb 20	4132, 4180, 4122, 4146	29560	3331	65410
Mar 20	4198, 4214, 4176, 4198	355	47	800
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4242, 4248, 4178, 4200	3170	323	17130
Feb 20	4278, 4282, 4214, 4232	4215	441	19230
Mar 20	4252, 4252, 4190, 4220	460	58	7205
Apr 20	4240, 4240, 4210, 4216	135	15	2670
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	802.9, 814.7, 797.6, 805.5	33430	2307	37960
Feb 28	803.6, 816.7, 800, 807.6	17590	1245	18850
Mar 31	805.3, 811.7, 801.9, 808.5	170	17	890
Apr 30	795, 795, 795, 795	10	1	10

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1283.6, 1293, 1276.5, 1289	130.32	300	238.68
Feb 28	1287.6, 1300.4, 1287.6, 1298	5.76	16	22.68
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4495, 4525, 4450, 4463	8760	784	10820
Feb 20	4468, 4512, 4445, 4464	15600	1262	10640
Apr 20	4450, 4464, 4412, 4429	6020	488	9470
May 20	4460, 4460, 4431, 4432	370	30	1070
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	917.6, 924, 908, 914.6	13935	1856	23810
Feb 20	917, 923.8, 906.2, 912.2	33705	3561	50650
Mar 20	915, 919.8, 901.2, 909.2	4285	423	23280
Apr 20	910.2, 913, 898.6, 903	555	84	2460
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4204, 4242, 4144, 4196	47495	5278	49650
Feb 20	4210, 4260, 4164, 4210	88555	10106	196285
Mar 20	4230, 4278, 4186, 4230	20460	2773	92730
Apr 20	4270, 4310, 4222, 4262	4980	768	17000
May 20	4324, 4326, 4292, 4326	395	67	1780
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	7378, 7401, 7324, 7356	6150	787	12605
Feb 20	7425, 7500, 7412, 7444	11055	1601	54475
Mar 20	7567, 7596, 7528, 7585	1050	171	3865
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	4476, 4488, 4441, 4484	6660	545	20730
Mar 20	4406, 4418, 4390, 4400	5230	466	15630
Apr 20	4419, 4428, 4390, 4401	250	25	1360
May 20	4400, 4400, 4400, 4400	10	1	20
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3925, 3925, 3883.5, 3885.8	1.8	13	3.6
Feb 14	3980.1, 4000, 3916.3, 3916.3	4.9	32	7.3
Mar 13	3783.1, 3783.1, 3783, 3783	0.3	3	0.8
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Jan 20	6336, 6370, 6213, 6234	3600	342	7180
Apr 20	6745, 6910, 6679, 6812	3480	333	8410
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	16140, 16140, 15940, 16035	654	158	1062
Mar 20	15740, 15785, 15625, 15695	393	120	1392
Apr 20	15450, 15450, 15350, 15385	60	20	486
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6264, 6468, 6180, 6446	3440	627	5430
Apr 20	6152, 6390, 6120, 6368	1790	336	4400
May 20	6320, 6400, 6320, 6400	40	5	65
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	141.3, 141.9, 140.8, 141.8	4577	2953	6547
Feb 28	140.45, 141.15, 140.35, 141.1	297	259	1107

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	446, 447.85, 446, 447.4	10842.5	3780	13722.5
Feb 28	447.3, 448.45, 447, 448.05	395	153	1697.5
Lead MCX(1 K)				
May 29	148.05, 148.05, 148.05, 148.05	1	1	1
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	152.55, 152.8, 152.4, 152.7	2624	1724	5212
Feb 28	152.4, 152.75, 152.3, 152.7	66	46	458
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	1023.7, 1030.9, 1023.7, 1029	10065	5742	3174

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Feb 28	1020.8, 1025.9, 1020.8, 1023.8	252	158	343.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	181.55, 182.15, 180.85, 181.9	13221

जेएनयू वापस लौट आएं छात्र: कुलपति

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जेएनयू हमले की वीडियो क्लिप और सूचनाएं साझा करने की अपील की

अर्चिस मोहन

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा घोषित बुधवार की एकदिवसीय हड़ताल को मंगलवार को कई छात्र संगठनों ने समर्थन देने की घोषणा की। वहीं, कई कार्यकर्ता तथा विपक्षी दलों के नेताओं ने रविवार रात्रि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों तथा शिक्षकों पर हमला करने वाले किसी भी नकाबपोश हमलावारों की पहचान करने एवं उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाना जारी रखा।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जनता से जेएनयू हमले की वीडियो क्लिप और सूचनाएं साझा करने की अपील की है। इस हमले के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और अपराध शाखा इस घटना की जांच कर रही है। अपराध शाखा ने सीसीटीवी फुटेज सहित साक्ष्य जुटाने के लिए स्थानीय पुलिस टीम के साथ सोमवार को परिसर का दौरा किया। पुलिस के मुताबिक एजेंसी घटना की सभी सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए तथा व्हाट्सऐप पर साझा किए गए वीडियो क्लिप खंगाल रही है।

जेएनयू में हुए हमले को लेकर मनोरंजन जगत की हस्तियों ने मुंबई में किया विरोध प्रदर्शन

प्राथमिकी दर्ज

जेएनयू के सर्वर रूम में तोड़फोड़ की घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि ये प्राथमिकी जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर 5 जनवरी को दर्ज की गई। जेएनयू प्रशासन ने तोड़फोड़ के सिलसिले में छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष समेत अन्य पदाधिकारियों के नाम दिए गए थे लेकिन पुलिस ने घोष या अन्य छात्रों के नाम प्राथमिकी में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं किए हैं। पुलिस ने बताया कि सर्वर बंद करने की शिकायत 3 जनवरी को और सर्वर रूम में तोड़फोड़ की शिकायत 4 जनवरी को दर्ज करवाई गई थी।

हमले के सिलसिले में सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की कई टीमें मंगलवार को जेएनयू पहुंची। एफएसएल की भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान विभागों की टीमें विश्वविद्यालय में हैं। भौतिकी टीम विश्वविद्यालय परिसर में नकाबपोश लोगों द्वारा छात्रों और अध्यापकों पर हमले में इस्तेमाल किए गए सरिया (रॉड) और पत्थरों जैसे सबूतों को एकत्र करेगी जबकि रसायन टीम वहां मौजूद रसायनों के नमूने जुटाएगी। जीव विज्ञान टीम अन्य साक्ष्यों सहित डीएनए नमूने एकत्र करेगी। फोटो विशेषज्ञों की एक टीम भी परिसर में मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एफएसएल से सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के लिए एक कंप्यूटर फॉरेंसिक टीम भेजने का अनुरोध किया है।

कुलपति की गुहार

जेएनयू कुलपति एम जगदीश कुमार ने मंगलवार को छात्रों से कहा कि वे बीती बातों को पीछे छोड़कर विश्वविद्यालय परिसर लौट आएं। कुमार इस बात को लेकर छात्रों और शिक्षकों केनिशाने पर हैं कि उन्होंने तब पर्याप्त कदम नहीं उठाए जब उन पर परिसर में नकाबपोशों द्वारा बेरहमी से हमला किया जा रहा था। कुमार ने कहा, 'सभी घायल छात्रों के प्रति मेरी संवेदना है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि जेएनयू परिसर एक सुरक्षित स्थान है।' उन्होंने कहा, 'मैं सभी छात्रों से आग्रह करता हूं कि वे परिसर लौट आएं।' जेएनयू परिसर में रविवार रात लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने परिसर में प्रवेश कर छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर दिया था और परिसर में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। बाद में प्रशासन को पुलिस को बुलाना पड़ा। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष सहित हमले में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे।

इस बीच मुंबई में जेएनयू हमले का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को मंगलवार सुबह गेटवे ऑफ इंडिया से आजाद मैदान ले जाया गया क्योंकि सड़क जाम होने की वजह से आम लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जाने की अपील की थी लेकिन वे नहीं माने इसलिए उन्हें आजाद मैदान ले जाया गया जिसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया।

हिंदू रक्षा दल का दावा

जेएनयू हमले में शामिल लोगों की पहचान के लिए पुलिस वीडियो फुटेज और चेहरे पहचानने की प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पुलिस दोषियों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज और चेहरे पहचानने की प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। विश्वविद्यालय में हुए हमले को लेकर दक्षिणपंथी समूह हिंदू रक्षा दल के दावे की जांच भी पुलिस कर रही है। हिंदू रक्षा दल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में जेएनयू परिसर में हुए हमले की कथित तौर पर जिम्मेदारी ली है। यह वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और फिर यह वायरल हो गया। इस वीडियो में एक व्यक्ति खुद को पिंकी चौधरी बताते हुए कह रहा है कि जो लोग 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' का सहारा लेंगे उनके साथ जेएनयू छात्रों और अध्यापकों जैसा ही सलूक किया जाएगा।

विपक्षी दलों की बैठक

कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेता 13 जनवरी को बैठक कर सकते हैं जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसा की स्थिति पैदा होने और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर बात होगी। *साथ में एजेंसियां*

जंगल में आग की वजह से ऑस्ट्रेलिया में तबाही।

संघ के कार्यक्रम में नहीं आएगी एक्सेंचर

तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां एक्सेंचर तथा जोहो सोमवार को ट्विटर पर एक बयानबाजी में घिर गईं। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक ट्विटर यूजर ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चेन्नई में कराए जाने वाले आईटी कार्यक्रम में इन दोनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारी कथित तौर पर शामिल हो रहे हैं।

जोहो के सह-संस्थापक तथा मुख्य कार्याधिकारी श्रीधर वेम्बू दो फरवरी को चेन्नई में होने जा रहे 'रिसर्जेंट भारत' में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। एक्सेंचर के प्रबंध निदेशक तथा ऑपरेशन प्रमुख (चेन्नई) राम एस रामचंद्रन को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होना था लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया।

सोमवार को देर रात्रि रामचंद्रन ने ट्वीट किया, 'मुझे नहीं पता कि यह गलतफहमी कैसे हुई। मेरा इस समूह से कोई जुड़ाव नहीं है और मैंने कभी इस कार्यक्रम में शामिल होने या बोलने के लिए अपनी सहमति नहीं दी।' नागरिकता संशोधन अधिनियम तथा एनआरसी के चलते देशभर में सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज और हाल ही में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुए हमले के बाद कई ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाई है।

कई लोगों ने कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को 'धार्मिक संगठनों' द्वारा आयोजित ऐसे आयोजनों में शामिल होने की अनुमति देने पर सवाल उठाया और एक्सेंचर तथा जोहो की सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। *बीएस*

ईरान विवाद: भारत के लिए सीमित विकल्प

सुलेमानी को श्रद्धांजलि देते ईरान कुद्स फोर्स के नए कमांडर इस्माइल घानी

आदिति फडणीस

अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से खाड़ी क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। क्षेत्र में 30 सालों में सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति देखी जा रही है। ईरान और खाड़ी मामलों के ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हालात में भारत खुद को बेहद जटिल स्थिति में पा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जितनी तेजी से इराकी संसद ने सभी अमेरिकी बलों को अपनी जमीन से बाहर जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया और अमेरिका ने भी उतनी ही फुर्ती से यह घोषणा कर दी कि वह इराक पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, ऐसे में तेजी से लिए गए ये फैसले गलत भी हो सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ से बात की और सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी कदम को लेकर चिंता जताई है, वैसे में भारत के लिए सुलेमानी की मौत के बाद इस क्षेत्र के भविष्य के घटनाक्रम को देखने के अलावा विकल्प बचता नहीं है।

हालांकि भारत ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना के लिए जिम्मेदार अमेरिका का नाम नहीं लिया जिसने इस घटना को अंजाम दिया था जिससे ईरान से थोड़ी दूरी का अंदाजा मिलता है। वहीं चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका का नाम दिया था। इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का विकल्प बेहद सीमित है क्योंकि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल के दौरान ही भारत अमेरिका के साथ मजबूती से खड़ा दिखने लगा जब भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुझान भी अमेरिका की तरफ ही है क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक तरह से यह घोषणा कर दी कि भारत चाहता है कि 'अगली बार ट्रंप सरकार'।

ईरान के पूर्व राजदूत के सी सिंह ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि संबंधों में बदलाव लाना बीते दिनों की बात है। उन्होंने बताया, 'सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अमेरिका के साथ देश के राजनीतिक नेतृत्व की सरगर्मी देखी जा रही है। ऐसे में भारत के लिए यह संभावना खत्म हो गई है कि वह ईरान और अमेरिका के बीच शांतिदूत की भूमिका निभा पाए।'

भारत की ईरान और इसके पड़ोस में परिसंपत्ति है और वह इसे बचाना चाहता है। इसके अलावा 85 लाख भारतीय नागरिक खाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तब देश के तेल एवं गैस के आयात पर असर पड़ेगा। ईरान के बंदरगाह चाबहार में निवेश पर भी संकट की स्थिति है जिसे तैयार करने में भारत मदद कर रहा है। इसके जरिये अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक के लिए व्यापार मार्ग बनेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कदम का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है और उनकी नीतियों से यह अंदाजा मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन ने सुलेमानी की मौत के बाद की रणनीति के बारे में संभवत: नहीं सोचा होगा।

भारत ने हाल के वक्त में ईरान के प्रति अपनी नाराजगी सार्वजनिक करनी शुरू कर दी। वहीं तेहरान देश के चाबहार बंदरगाह उद्यम में उतना सहयोग नहीं कर पा रहा था और इसने कश्मीर में कुछ 'अतिवादिता' को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। हालांकि पहले सुलेमानी देश के सहयोगी रहे हैं और वह अफगानिस्तान में तालिबान के साथ वार्ताकार भी रहे हैं। लेकिन एक व्यापक भूराजनैतिक खेल में भारत के लिए अमेरिका एक तरजीही साझेदार है जबकि ईरान एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सहयोगी बना रहेगा।

तकनीक के साथ मानव स्पर्श वाला होगा निऑन

पृष्ठ 1 का शेष

कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री

निऑन में अलग क्या होगा, पूछे जाने पर मिस्त्री ने कहा कि यह एआई असिस्टेंट या कोई अन्य वॉयस असिस्टेंट की तरह नहीं होगा, बल्कि इसमें इंसानी पहलू शामिल होगा और इससे बात करने के दौरान ऐसा लगेगा जैसे कोई वास्तविक आदमी से बात हो रही है। अन्य एआई उपकरण इंटरनेट इंटरफेस पर काम करते हैं और सवालों के जवाब सर्च करके देते हैं। लेकिन निऑन के मामले में कंपनी का दावा है कि इसमें मानव की भावनाएं और अभिव्यक्ति अहम पहलू होंगी, जो कंपनी के कोर आर3 तकनीकी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। कोर आर3 कई तकनीक का संयोजन है, जिनमें व्यवहारात्मक तंत्रिका नेटवर्क (बीएनएन), ईजीआई और कंप्यूटेशनल रियलिटी शामिल है, जो निऑन को जीवंत रियलिटी और रियल-टाइम रिस्पॉन्स प्रदान करेगी। मिस्त्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म पहले कैप्चर किए गए डेटा को वॉयस या फेस प्रदान कर सकता है और यह वास्तविक आदमी की तरह 20 मिली सेकंड से भी कम समय में इंटरेक्ट कर सकता है।

आईआईटी बंबई और मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के पूर्व छात्र रहे मिस्त्री ने कहा, 'इसके पीछे हमारा विचार यह है कि निऑन केवल अन्य रोबोट की तरह काम नहीं करे क्योंकि लोगों के पास यह पहले से मौजूद है। लोगों के पास फोन में एआई उपलब्ध है। हम निऑन को तकनीक के साथ मानव स्पर्श वाला बनाना चाहते हैं। यह आपके दोस्त की तरह है जो आपसे बात करेगा।' निऑन फिलहाल थर्ड-पार्टी मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं या यूजर्स द्वारा मुहैया कराए गए निर्दिष्ट जानकारी या इंटेलिजेंस जैसे विषयों को समझ सकता है। उदाहरण के लिए अगर आईसीआईसीआई बैंक अपने यहां निऑन को प्रतिनिधि के तौर पर रखना चाहे तो वे इस क्षेत्र की जानकारी मुहैया करा सकते हैं और निऑन इंटरफेस की तरह काम कर सकता है।

अगले चरण में लैब्स आगामी तकनीकी प्लेटफॉर्म स्पेक्टरा का इस्तेमाल कर इसे और बुद्धिमान बनाने पर काम कर रहा है। स्पेक्टरा को इस साल के अंत में नियोवर्ल्ड 2020 में पेश किया जा सकता है। निऑन को ज्यादा दक्ष बनाने में स्पेक्टरा की अहम भूमिका होगी और इसकी मदद से यह इंटरैक्ट कर सकेगा और सही भावनाओं के साथ यह चीजों को याद रख सकेगा। मिस्त्री ने कहा, 'कोर आर3 प्लेटफॉर्म में निऑन के विजुअल पहलू पर ध्यान दिया गया जबकि स्पेक्टरा के साथ यह बुद्धिमता, याददाश्त, भावनाएं और संबंधित क्षेत्र की जानकारी आदि से लैस होगा।'

कंपनी भारत सहित विभिन्न साझेदारों से साल के अंत में इसका बीटा परीक्षण करने के लिए बात कर रही है।